>

Title: Further discussion on Construction of canals through Ken-Betwa River linking project to overcome the problem of water scarcity and stray cows in the Bundelkhand region (Discussion not concluded).

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैं बहुत आभारी हूं कि आपकी स्वेच्छा से कृपा मिली। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक महत्वपूर्ण विषय है जिससे सारा सदन चिंतित है, वे चाहे सत्तापक्ष के लोग हों या प्रतिपक्ष के लोग हों। कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी ने अपने क्षेत्र बुंदेलखण्ड के संबंध में यह विषय उठाया था कि बुंदेलखण्ड में लगातार वर्षों से पानी के संकट के कारण स्थिति यह है कि वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। पानी के संकट व चारे की कमी के कारण लोग अपने जानवरों को खुला छोड़ दे रहे हैं, जिसको अन्ना प्रथा कह रहे हैं। इस कारण वहां के किसानों की फसल को बहुत नुकसान होता है। बुंदेलखण्ड चाहे उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो, या मध्य प्रदेश का हिस्सा हो, उन दोनों इलाकों में पानी के संकट के कारण जलस्तर में गिरावट आ रही है, जिसके कारण निश्चित तौर पर बड़ी पथैटिक कंडीशन हो गई है। उन्होंने इस विषय को लिया और आपने कृपापूर्वक इसको स्वीकार किया।

महोदया, यह संकट अब केवल बुंदेलखण्ड में नहीं है, यह संकट केवल कुछ क्षेत्र तक सीमित नहीं है, आज यह संकट कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक है। आज देश के सभी राज्यों में कहीं न कहीं पानी का ऐसा संकट है कि इसके समाधान के लिए सदन को भी सोचना होगा। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो पानी का संकट है और जिस पानी के संकट के समाधान के लिए आज तमाम राज्यों में जिस तरह की मतभिन्नता है, वह अत्यंत गंभीर है। राज्यों में आपस में लिटिगेशन्स हैं। राज्यों में आपस में आंदोलन हैं, चाहे वह तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो या देश का कोई भी राज्य जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखण्ड हो।

महोदया, इसे देखते हुए जिस तरीके से एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया, वह इसीलिए कि प्रधान मंत्री जी की इच्छा थी कि हम किस तरह से आने वाले दिनों में वाटर कन्जर्वेशन कर सकें या वाटर हार्वेस्टिंग या रेन हार्वेस्टिंग कर सकें, क्योंकि यही इसका एक समाधान हो सकता है।

सभापति महोदया, एक बात से आप सहमत होंगी कि आज इस मंत्रालय को बनाने के लिए पहली बार अगर प्रधान मंत्री जी ने यह फैसला किया, तो निश्चित तौर पर इसलिए किया कि आज पानी एक ऐसी चीज है, जिसे अगर हमने प्रिजर्व नहीं किया या उसका संचयन नहीं किया, तो हम पानी का निर्माण नहीं कर सकते हैं। पानी के संकट का समाधान केवल पानी को बचाने से ही हो सकता है और किसी चीज से नहीं हो सकता है। आज मुझे चंदेल साहब के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया गया है।

आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के 13 जनपदों में जो स्थिति है, करीब 70 हजार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। वर्ष 2003 से जल संकट शुरू हुआ है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार बुंदेलखंड के इंटरनल इलाकों से जो माइग्रेशन हो रहा है, उसका मुख्य कारण पानी है। पानी का संकट लोगों के सामने गम्भीर चुनौती इसलिए भी हो गया है कि सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का आंकड़ा है कि वहां के जो कुएं थे, जिनसे लोग पानी निकालकर इस्तेमाल करते थे, उन कुओं के पानी का जल स्तर 61 परसेंट तक नीचे चला गया है। नीति आयोग ने भी वाटर क्राइसिस पर अपनी रिपोर्ट दी है कि 600 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जो आज पानी के गम्भीर संकट से गुजर रहे हैं। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जल संकट से सर्वाधिक प्रभावित हैं। हमें इस बात की चिंता करनी होगी कि ऐसे कौन से कारण हैं, जिनके कारण पानी का यह संकट खड़ा हुआ है और किस तरह से उन पर काम किया जा सकता है। जल शक्ति मंत्रालय को बनाने के पीछे प्रधान मंत्री जी की परिकल्पना थी। उन्होंने वर्ष 2014 में मिशन मोड के रूप में स्वच्छता अभियान की शुरूआत की थी। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से प्रधान मंत्री जी ने राजधानी दिल्ली की सड़क पर झाड़ू चलाया। यह पूरे देश के लिए संदेश था। हमारी सरकार ने केवल स्वच्छता अभियान का नारा ही नहीं दिया अपितु नौ करोड़ घरों में शौचालय देने का काम किया है। पहले महिलाओं

को शौच जाने के लिए सांय काल का इंतजार करना पड़ता था। मैं समझता हूं कि यह अभियान अपने आप में क्रांतिकारी है। पिछले पांच सालों में देश के तमाम राज्यों में जागरुकता आयी है और अब लोगों को सार्वजनिक रूप से गंदगी फैलाने पर अपराध बोध होता है। इससे कहीं न कहीं पूरी दुनिया में हमारे देश के प्रति नजरिया बदला है। अब भारत में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शहरों की सफाई होती है। देश की आजादी के कई सालों बाद भी करोड़ों परिवारों के पास घर नहीं था और घर था तो शौचालय नहीं था। गांव से लेकर शहरों तक गंदगी थी। पूरी दुनिया का नजरिया था कि भारत में इसको लेकर कोई चिंता नहीं है। पिछले पांच सालों में हमारी सरकार ने ऐसी परिस्थितियां तैयार की हैं कि पूरे देश में स्वच्छता का वातावरण पैदा हुआ है। स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, सामाजिक या सार्वजनिक स्थान, ऐसी सभी जगहों पर स्वच्छता के प्रति लोगों के मन में चेतना आयी है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दो दिन हमारे लोक सभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने स्वच्छता अभियान को बढ़ाने के लिए लोक सभा और राज्य सभा के हम सभी सांसदों को लोक सभा परिसर में स्वच्छता अभियान को बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। यह हम सभी का सौभाग्य है कि हम प्रधान मंत्री जी के स्वच्छता के अभियान के साथ अपने गांव में भी जुड़े थे और स्वच्छता अभियान में शामिल थे। संसद में स्पीकर साहब ने उस काम को बढ़ाया है।

महोदय, जब एक अभियान इस तरह से मूर्त रूप ले रहा है तो मैं समझता हूं कि पानी के संकट को वर्ष 2019 में हमारी सरकार बनने के बाद प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हमें जल संकट के समाधान के लिए जल का संरक्षण है। इसके लिए हमारे युवा मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के ऊपर जिम्मेदारी दी गयी है। अभी तक उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि देश के 17.87 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से अभी तक केवल 3.27 ग्रामीण नल और पाइपलाइन के द्वारा पानी मिलता है।

यह स्वाभाविक है कि देश सन् 1947 में आज़ाद हुआ था और 1947 से आज हम वर्ष 2019 में खड़े हैं और आज भी 2019 में देश के करोड़ों-करोड़ परिवारों के पास स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। मैं समझता हूं कि यह इस देश के लिए कितनी सोचने और चिंता करने का विषय है। शायद यह परिस्थितियां सन् 1947

से देश की आज़ादी के बाद से अब तक निर्मित थीं। इस बात की चिंता पिछली सरकारों में भी हो सकती थी, लेकिन मैं आज निश्चित तौर से इस बात के लिए बधाई दूंगा कि प्रधान मंत्री मोदी जी ने यह तय कर लिया है कि वर्ष 2024 तक हम देश के हर घर में पाइपलाइन से पेयजल पहुंचाने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि यह दुनिया में एक क्रांति है, जैसे उन्होंने 'आयुष्मान भारत' के लिए किया है। आज ओबामा केयर की बात हो रही थी। इसी तरह मोदी केयर की चिंता है कि 10 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये परिवार के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। यह सिर्फ किसी सरकार की इच्छा शक्ति से ही हो सकता है और किसी सरकार के संकल्प से ही हो सकता है।

यह विपक्ष हमसे सवाल करता है कि आखिर इतनी बड़ी योजना घोषित हो गई है, तो इसके लिए पैसा कहां से आएगा, वह 50,000 करोड़ रुपये कहां से आएंगे? प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा हुई और वह 12 करोड़ परिवारों को मिलेगा। इस बार के बजट में इसके लिए 75,000 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है। मैं समझता हूं कि आज किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए, निश्चित तौर से किसानों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, चाहे 75,000 रुपये करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ परिवारों और आयुष्मान भारत के लिए 50,000 करोड़ रुपये हों, अगर वर्ष 2024 तक हर घर में पाइपलाइन से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का संकल्प लिया है, तो निश्चित तौर से हमारी सरकार और इस नए मंत्रालय के नेतृत्व में हर घर में पानी पहुंचेगा और कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचेगा।

महोदया, हम पिछली सरकरों की कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में देश की 100 प्रतिशत आबादी के सापेक्ष अभी तक 18.33 प्रतिशत आबादी को ही केवल नल से पानी उपलब्ध हो रहा है। मैं समझता हूं कि आज तक 50 प्रतिशत लोगों के लिए देश की आजादी का क्या अर्थ है। हमने जंगे आज़ादी की ब्रितानिया हुकूमत से गुलामी की दास्तां की जंजीरों से मुक्ति दिलाई। हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी थीं, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाई और शहादत दी, हंसते-हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। अगर

ब्रितानिया हुकूमत की गोली लगी, तो अपनी बहनों को दिए हुए वचन के मुताबिक अपने सीने पर गोलियां खाईं। उस कुर्बानी की कीमत यह थी कि वर्ष 2019 तक केवल 18 प्रतिशत घरों में स्वच्छ पेयजल मिल सके। हम पानी जैसी बुनियादी चीज न दे सकें। आज मैं समझता हूं कि वह सबसे बुनियादी चीज थी और लोगों का हक था कि उनको कम से कम स्वच्छ पेयजल मिल सके। उस स्वच्छ पेयजल के बुनियादी हक को पहुंचाने का संकल्प अगर पहली बार किसी सरकार ने सोचा है, तो वह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने सोचा है। यह संकल्प निश्चित तौर से केवल संकल्प नहीं होगा, बल्कि यह सपना साकार होगा। इसीलिए, वर्ष 2019-20 के केन्द्रीय बजट भाषण में...(व्यवधान)

माननीय सभापति: मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि इस संकल्प पर पहले ही चार घंटे की चर्चा हो चुकी है और इस प्रकार इस चर्चा पर आबंटित समय लगभग समाप्त हो चुका है। चूंकि उक्त संकल्प पर हो रही चर्चा में 12 और सदस्यों को भाग लेना है, इसलिए सभा को इस संकल्प पर अधिक चर्चा करने के लिए समय को बढ़ाना होगा। इसलिए, क्या सभा सहमत है कि संकल्प पर चर्चा हेतु समयावधि को दो घंटे और बढ़ा दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य : हां-हां।

माननीय सभापति : ठीक है, समयावधि को दो घंटे और बढ़ाया जाता है।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदया, जब 2019-20 का केन्द्रीय बजट हमारी वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया था, तो उसमें सबसे ज्यादा जो फोकस हुआ है, वह जल जीवन मिशन के लिए हुआ है। जल जीवन मिशन का केवल यही उद्देश्य था कि हम वर्ष 2024 तक सभी घरों में निश्चित रूप से जल को पहुंचाने का काम करेंगे। आज केवल हमने जल जीवन मिशन नहीं बनाया है, हमने कोई स्लोगन दे दिया है या किसी कार्यक्रम का नाम दे दिया है, बल्कि उस जल जीवन मिशन को क्रियान्वित करने के लिए, जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए, हमने जल शक्ति अभियान का निर्धारण किया है, उसका रोड मैप बनाया है।

उसने चिन्हित किया है कि देश के 256 जिले ऐसे हैं, जिसमें 1592 ब्लॉक्स का चयन किया गया है कि जहां पर पानी का संकट था। उन 1592 ब्लॉक्स में से

312 ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर इतना पानी निकाला जा चुका है, इतना अति दोहन हो चुका है कि गंभीर संकट पैदा हो गया है। इसी तरह से 1186 ब्लॉक्स में भी पानी का संकट पैदा हो गया है। उन ब्लॉक्स के लोगों को नीचे तक, डीप बोरिंग के बावजूद भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि लगातार पानी को हम यूज़ करते रहते हैं। अगर पानी का कंज़र्वेशन हम नहीं करेंगे, पानी का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में यह क्राइसिस दुनिया के सामने हो रहा है, भारत के सामने हो रहा है, लेकिन समय रहते हुए हमारी सरकार ने सोचा है। मैं कह सकता हूँ कि उस पर काम होगा।

महोदया, आज कम से कम जो हमारे 94 ब्लॉक्स हैं, उनमें भी भू-जल की कम उपलब्धता है। हमारे माननीय मंत्री जी ने 5-6 कार्यक्रमों पर सभी मंत्रियों को पत्र भी लिखा। सभी राज्य सरकारों को 11.06.2019 को कहा है। मतलब सरकार बनते ही सबसे पहले जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह जी के द्वारा सभी संबंधित मंत्रियों को, राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ एक अस्थायी जल-प्रबंधन के लिए लिखा गया है क्योंकि मान लीजिए कहीं अगर बुंदेलखंड में पानी का संकट है तो हम ट्रेन से पानी पहुंचा दें। कहीं कर्नाटक में, कहीं महाराष्ट्र में, कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं बिहार में या किसी राज्य में पहुंचा दें तो वह एक अस्थायी समाधान होगा। निश्चित तौर से अस्थायी समाधान के लिए हमें जो कार्ययोजना तैयार करनी होगी, उस संबंध में कम से कम एक अस्थायी जल प्रबंधन के मुद्दे पर चर्चा हमारे इस जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू की है और माननीय मंत्री जी ने पहल की है। निश्चित तौर से मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि जो मिशन उन्होंने शुरू किया है और बढ़ाया है, उस पर हमारे राज्यों के सहयोग से आने वाले दिनों में संकट दूर हो सकेगा।

इसी तरह से प्रधान मंत्री जी ने भी 08.06.2019 को देश के एक-एक गांव के सरपंचों को, चाहे वह जल संरक्षण के लिए या वर्षा जल-संचयन, वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर कंज़र्वेशन एण्ड वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए उसके महत्व को रेखांकित करते हुए आज पानी का इतना मूल्य है, पानी की कितनी आवश्यकता है, उसके बारे में खुद प्रधान मंत्री ने स्वयं देश के सभी राज्यों के सरपंचों को अपनी तरफ से पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि यह केवल एक केन्द्र सरकार या केवल प्रशासन के

माध्यम पर छोड़ देंगे तो निश्चित तौर से जल संरक्षण की, जब तक कि स्वच्छता अभियान की तरह से यह आंदोलन नहीं बनेगा, तब तक शायद इसको हम जन आंदोलन नहीं बना सकते हैं। आज जल संरक्षण को एक जल आंदोलन बनाने के लिए हमारे सरपंच, जो एक स्थानीय स्तर पर हैं। ...(व्यवधान) मैडम, अभी तो आपने हमें स्वेच्छापूर्वक कहा था। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मैंने अभी टाइम देखा है तो आप 23 मिनट पहले बोल चुके हैं, 17 मिनट अभी बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: थोड़ी देर आप टाइम मत देखिए, सदन की तरफ देखिए।

माननीय सभापति : जगदम्बिका जी, टोटल 43 मिनट्स हो गए हैं तो इसको आप वाइंड-अप कर दीजिए। और भी लोग बैठे हैं।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: मैडम, हम कर देंगे। अभी तो बोलने दीजिए।

मान लीजिए कि कोई कार्यक्रम शुरू हो रहा है तो इस कार्यक्रम में जब हम आगे करेंगे, आज पूरी दुनिया में यह बात लिखी जा रही है कि किस तरीके से जल संरक्षण किया जाए। हमारी तो जो इंड्स रिवर थी, उसी के नाम पर हमारे देश का भी नाम पड़ा है। वे भारत की लैण्ड ऑफ सैवन रिवर्स कहलाती भी है। आप अगर संजीव सन्याल की बुक को देखें, मतलब उसी समय उन्होंने नाम दिया था कि हमारी यह जो इंड्स रिवर है, उसी के नाम पर देश का नाम पड़ा है। आज अगर उस पानी के संकट को दूर नहीं किया गया तो केवल सूखा ही नहीं पड़ेगा, बेरोज़गारी भी बढ़ेगी, जो पैरलल वॉटर क्राइसिस है, उससे भी कठिनाई होगी। इस तरीके से इस कठिनाई के बाद जो स्थितियां बनेंगीं, उसमें आगे हम कैसे काम करेंगे? सरकार ने कुछ अपनी पॉलिसीज़ की हैं। चाहे वह जल-जीवन मिशन हो या सन् 2024 तक हर घर को पानी की बात हो या नैशनल रूरल ड्रिंकिंग वॉटर प्रोग्राम हो, यह भी एक बड़ा प्रोग्राम है। नैशनल मिशन फॉर क्लीन

गंगा हो या जल-शक्ति मिनिस्ट्री स्टैब्लिश की हो, मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करना पड़ेगा।

जो ईजमेंट एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट करना पड़ सकता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सब को रेशनलाइज करते हैं, वाटर को भी रेशनलाइज करे। कैसे रीसाइक्लिंग कर सकते हैं या हम क्रॉप के भी पैटर्न को चेंज करें। जिन क्रॉप्स में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, उस तरह से हम कुछ चेंज इन क्रॉप पैटर्न करें, जिससे कम पानी की आवश्यकता हो। लोकल पार्टिसिपेशन की भी आवश्यकता है। इसी तरह से मिहिर शाह की कमेटी ने भी रिकमंड किया था कि एक नेशनल वाटर कमीशन इस्टेब्लिश किया जाए। मुझे लगता है कि आज इसकी भी ज़रूरत होगी। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, क्योंकि बुंदेलखंड के जल संकट पर यह चर्चा है। आज पानी सब के लिए एक्सेसिबल हो, पानी अविरल हो या पानी एफोर्डेबल हो। इस बात पर कम से कम हर आदमी का अधिकार भी बनता है। उस अधिकार के अंतर्गत यह करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो जल संरक्षण है वर्षा का जल भंडारण है, उसके संबंध में सरकार की कौन सी योजना होगी। पहले पारंपरिक और अन्य जल भंडार ट्रेडिशनल थे। आप देखते हैं कि उन जल भंडारों का वाटर लेवल इसलिए ऊपर होता जा रहा है। पुराने ज़माने में ब्रिटिशर्स ने नेपाल की फुटहिल्स में बांध बनाए थे या तालाब बनाए थे। आज जिस तरह से मिट्टी का क्षरण हो रहा है, जिस तरीके से परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, कल बिहार के 32 सदस्यों ने कहा कि अगर नेपाल में बारिश शुरू होती है, चाहे बिहार की कोसी हो, बानगंगा हो, करनाली हो, जलकुण्डी हो, उससे जिस तरह का सैलाब आता है, उसके साथ जो मलबा आता है, वह हमारे रिवर बेड्स को भी ऊपर करता जा रहा है और हमारे तालाब को भी ऊपर कर दिया है, जिसके कारण हम कंजर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में आप आगे क्या सोचेंगे, क्योंकि अगर तालाब को हम गहरा नहीं कर रहे हैं या हम निश्चित तौर से लाइन डिपार्टमेंट के बजाय, हम यह तय कर दें कि ब्लॉकों में, क्षेत्रों में हर गाँव के तालाब की हम खुदाई करेंगे, नए तालाब की खुदाई करेंगे।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री अनुराग शर्मा।

श्री जगदांम्बेका पाल : मैं दो-चार मिनट में कनक्लूड करूँगा।

माननीय सभापति : आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल: हमने सोचा था कि आपने टाइम दे दिया है।

माननीय सभापति : आपको बोलते हुए 45 मिनट हो गए हैं।

श्री जगदम्बिका पाल: मैं वाटर शेड विकास के लिए आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। गहन वनीकरण करना होगा। केन और बेतवा की बात हुई है। केन और बेतवा की इंटरलिंकिंग...(व्यवधान) मैं कहता हूँ कि आज बुंदेलखंड के संकट को लेकर चर्चा है। पानी का संकट बुंदेलखंड में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। जो यह डार्क जोन है, इतने ब्लॉक्स हैं, इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें भी निश्चित तौर से एक गम्भीर संकट है। मैं समझता हूँ कि आज इस प्रस्ताव के माध्यम से और प्रधान मंत्री जी के प्रयास से एक जन आंदोलन बनाने की बात चल रही है। हमारा मंत्रालय भी कार्य योजना बनाने के लिए काम कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में एक गम्भीर विषय जो पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल जी ने उठाया है, उस पर सरकार का ध्यान जाएगा। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ और उनका समर्थन करता हूँ।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, एक सूचना है कि अभी जगदम्बिका जी को इतना समय मिल गया, लेकिन अभी बहुत लम्बी सूची है। हर सदस्य को समय मिल पाए तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब 10 से 15 मिनट के बीच में अपनी बात समाप्त करें, ताकि सब को अपनी बात कहने का मौका मिले।

श्री अनुराग शर्मा।

श्री अनुराग शर्मा (झांसी): सभापति महोदया, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं झांसी से आता हूँ। दूसरी चीज यह कहना चाहूँगा कि हमारे वहाँ दो

बहुत पवित्र स्थल हैं- पीताम्बर माँ का शक्ति पीठ और राम राजा का मंदिर। उन दोनों का आशीर्वाद इस पूरे सदन पर रहे और आप सब पर रहे।

महोदया, हम बुंदेलखंड के लोग हैं और बुंदेलखंड इस देश में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। यह बहुत वीरों की भूमि रही है। यहाँ से हमेशा वीर आए हैं, चाहे आला उदल की कहानियाँ हों, चाहे हमारी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की कहानियाँ हों, हमारे वहाँ से दुर्गावती जी रही हैं, हमारे वहाँ चन्देलाओं का राज्य रहा है, हमारे वहाँ बुन्देलाओं का राज्य रहा है, इस क्षेत्र पर खंगाराओं और मराठाओं ने राज्य किया है। इन सबने यहाँ अपनी छाप छोड़ी है। इन्होंने बुंदेलखंड में सम्पूर्ण रूप से 8 हजार से ज्यादा तालाब बनवाए। यह वही धरती है, जो खुजराहो के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तब से हमारे वहाँ एक व्यापक रूप से और इतने बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम होता रहा है। इन्होंने वहाँ बावड़ियाँ बनवाईं, ताल खुदवाये और बड़े-बड़े मंदिर बने, लेकिन अब हमारे वहाँ जल के अभाव से, जैसे किसी ने बहुत पहले कहा था कि अगर जल न हो तो जल जायेगा जग, तो आज बुंदेलखंड जल रहा है। आज वह अवसर भी है, आज मंगल पांडे जी की जयंती है। इन्होंने सन् 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरूआत की थी। मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। महान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झाँसी के बारे में कुछ लिखा था।

सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकुटी तानी थी,
बूढ़े भारत में आई फिर से नयी जवानी थी,
गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी,
दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी।
चमक उठी सन सत्तावन में, वह तलवार पुरानी थी,
बुंदेले हरबोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी॥

यह सब इस देश में बच्चों को कंठस्थ याद है, हम सबको याद है और जो इतनी वीर भूमि रही है, आज वहाँ उस गरीबी के हाल में, क्योंकि पानी के अभाव से वह पूरा का पूरा क्षेत्र जल रहा है, इससे दिल को बहुत चिंता होती है, इससे हम सबका दिल टूटता है, हमारे बच्चों का भविष्य नहीं रह गया है। इसमें मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। इस देश पर पुलवामा का एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था। उसके अगले दिन भी आदरणीय प्रधान मंत्री जी झाँसी आये और विशेष रूप से उन्होंने हमारे बुंदेलखंड के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया, जिसमें से वे 9 हजार 21 करोड़ रुपये की पेयजल योजनाओं के लिए बोलकर गए। अगर ये पेयजल की योजनाएं हमें सचमुच में चलानी हैं और उधर पेयजल पहुँचाना है, तो पेयजल की योजना तो बन जाएगी, पेयजल के लिए लाइने बिछ जाएंगी, पर जल कहाँ से आएगा। यह जल लाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी का तो विशेष रूप से आभार करना चाहता हूँ कि उन्होंने बुंदेलखंड की आवाज सुनी और बुंदेलखंड ने उनकी आवाजा सुनी। जितनी भी बुंदेलखंड में सीटें रही हों, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश की सीटें रही हों या मध्य प्रदेश की सीटें रही हों, हमारे वहाँ से सारे के सारे सांसद जीतकर आए हैं। हमारे सांसद केवल जीते ही नहीं हैं, बल्कि सभी सांसद लाखों वोटों से जीतकर आए हैं। सब की जीत रिकॉर्ड रही है। हमारे प्रधान मंत्री जी वहाँ आए थे। यह तो वैसे ही वाली कहानी हो जाती है, जैसे हनुमान जी से एक जड़ी बूटी माँगी गई थी और वे पूरा पहाड़ उठा लाए थे।

जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा कि हम तो इस कोशिश में हैं कि एक नदी को उठाकर दूसरी नदी में ले आएं। मैं यह चाहूंगा कि इस पर हमारे यहां काम होता रहे।

महोदया, मेरा आग्रह है कि अगर प्रधान मंत्री और हमारे जल शक्ति मंत्री जी इस योजना को चालू करवा दें तो वे हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। बुंदेलखण्ड में जब भी कोई बहुत वीर या कोई बहुत अच्छी चीज होती है तो उसके लोकगीत बनते हैं, जो एक नहीं, दस नहीं, सौ नहीं, बल्कि पाँच-पाँच सौ सालों के बाद भी गाए जाते हैं। हमारे यहां आल्हा होते थे। आल्हा-उदल की कहानी ऐसे ही सुनाई

जाती है। मेरा आग्रह यही है कि अगर हमारे जल शक्ति मंत्री जी ने यह कार्य करा दिया तो 500 सालों के बाद भी हम इनके भी गीत गाएंगे।

महोदया, मैं जल शक्ति मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जहां से वे आते हैं, वह मेरी पैतृक भूमि है। मैं भी राजस्थान का ही हूं। मेरे पूर्वज वहीं से निकल कर आए। राजस्थान में भी हमेशा जल संकट रहा, पर चूंकि मैं उस जगह से वाक़िफ हूं, मैं अपने गांव जाता रहता हूं तो वहां इतनी बुरी हालत नहीं है, जितनी कि बुंदेलखण्ड में है। उनसे यही आग्रह रहेगा कि कभी हमारे साथ आएं और कभी जरा देख कर जाएं कि यह परियोजना हमारे लिए कितनी जरूरी है। मैं इनको यह आश्वासन दिलाऊंगा कि हमारे मुख्य मंत्री आदरणीय महाराज योगी जी इस परियोजना को लाने में यू.पी. की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदया, अब मैं बताना चाहता हूं कि पानी के अभाव से कितनी समस्याएं खड़ी होती हैं। जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है, वह कल्टीवेशन की है, एग्रीकल्चर की है। आप कहीं के भी आंकड़े निकाल लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि बुंदेलखण्ड में अक्सर एक ही फसल होती है। हमारे यहां चावल, धान की फसल नहीं लगती क्योंकि वहां पानी नहीं है। हमारे वहां पर अगर कोई फसल लगाई जाती है तो थोड़ी बहुत मूंगफली लगाई जाती है और बाद में थोड़ी सरसों लगाई जाती है। अगर इस देश में सरसों का प्रति हेक्टेयर आउटपुट 25 क्विंटल है तो हमारे बुंदेलखण्ड में मात्र चार या साढ़े चार क्विंटल है। अगर हमारे देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर आउटपुट 3200 या 3400 है तो बुंदेलखण्ड में यह 2700 या 2800 पर ही रह जाता है। इस तरह हमारे यहां न तो किसानों को पैसा मिल पाता है और न ही उसकी जमीन उतनी उपजाऊ रह जाती है।

मैडम, बुंदेलखण्ड में तो एक ही कहानी है कि जब इतने साल बारिश नहीं होती है तो अगर कोई हमसे पूछता है कि वहां क्या उग रहा है तो हम कहते हैं - पत्थर। हमारे यहां पत्थर ज्यादा उगते हैं, फसलें कम।...(व्यवधान) जी, पत्थर फसल से महंगा है, पर उसकी माइनिंग भी करनी पड़ती है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है।

महोदया, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पहले हमारे यहां एवरेज रेनफॉल 800-900 एम.एम. था और पिछले चार सालों से गिरकर आज वह मात्र 400-450 एम.एम. रह गई है। हम जो इन दो नदियों, केन और बेतवा को जोड़ने की बात करते हैं, ये उत्तरायण नदियां हैं, उत्तर की ओर जाती है। इनका जो वाटरशेड एरिया है, वहां पर 1100 एम.एम. से अधिक बारिश होती है। मध्य प्रदेश में अक्सर बारिश ठीक हो जाती है। इन नदियों में इतना पानी आ जाता है कि हमारे यहां बाढ़ आती है और 70 से 80 प्रतिशत इनका वाटर का रन-ऑफ हो जाता है। यह पानी सीधा यमुना जी में चला जाता है और वहां से महासागर में चला जाता है, जिस पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बुंदेलखण्ड एक रेन शैडो एरिया में पड़ता है। बारिश हम से 400 या 600 किलोमीटर दूर होती है। हमारे वहां वह होना जरूरी नहीं है, पर वह पानी हमारे यहां से गुजरता है और कभी-कभी यह हमारे यहां तबाही भी मचाता है।

हमारे यहां कभी-कभी तबाही भी हो जाती है। अगर रिवर्स लिंकिंग का काम हो गया, तो हम तबाही से बचेंगे और लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हम पहले यूपी के कृषि के लिए 15 परसेंट कंट्रीब्यूट करते थे, लेकिन आज यह गिरकर सात परसेंट रह गया है। बाकी सभी जगह हरित क्रांति हुई और वहां उत्पादन बढ़ता चला गया, लेकिन हमारे यहां उत्पादन घट गया। इस साल भी हमको नहीं लग रहा है कि इतनी बारिश हो पाएगी। बुंदेलखंड में अक्सर चार साल सूखा पड़ता है और एक-दो साल कभी बारिश हो जाती है। इस वजह से हमारे यहां अन्ना प्रथा शुरू हो गई। उसकी इतनी भयानक स्थिति हो गई कि जिस किसान के खेत में गलती से कुछ लग गया और कुछ फसल भी हो गया, तो अक्सर जानवर उनकी फसल में घुस जाते हैं, क्योंकि उनको खाने को कुछ नहीं मिलता। इससे खेत के खेत उजड़ जाते हैं और उस किसान का परिवार तबाही की ओर चला जाता है।

सभापति महोदया, अगर हमारे यहां जल होता, तो हम चारा भी उगा लेते, हमारे यहां लाइव स्टॉक भी ठीक हो जाता और अन्ना प्रथा की समस्या भी कम हो जाती। आज जब किसान अपने जानवर को खिला नहीं सकता, तो वह उस गाय

का क्या करेगा? वह उस गाय को छोड़ देता है। जब आप गाय को खिला नहीं सकते, तो गाय के मिल्क का प्रोडक्शन कहां से होगा? अगर हम अपने यहां औसतन मिल्क प्रोडक्शन देखें, तो दो-तीन लीटर से ज्यादा मिल्क नहीं निकलता। हमारे यहां को-ऑपरेटिव बनाने की कोशिश की गई, एक-दो डेयरीज़ वाले भी आए, लेकिन जहां 100-200 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता हो, तो वहां यह काम संभव नहीं। हमारे यहां मिल्क कलेक्शन के चक्कर में सभी डेयरीज़ बंद हो चुके हैं। पानी के अभाव से हर चीज़ पर फर्क पड़ता है। इस देश में एक बार विशेष रूप से मेलन्यूट्रिशन पर चर्चा हो चुकी है। आज बुंदेलखंड में मेलन्यूट्रिशन और एनिमिक इतना ज्यादा बढ़ता चला गया है कि हमारे यहां औसत से 25 परसेंट लेडीज़ एनिमिक पाई गईं। आज वहां इतनी बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि हम अपना पैदावार नहीं कर पाते हैं। वहां ताल सूख गए हैं, नदियों में पानी नहीं है, नहरों में हम कुछ दे नहीं पाते हैं। हमारे जो कुछ ताल रह गए हैं, उसी में से इंसान भी पानी पीता है और उसी में से जानवर भी पानी पीता है। उसके लिए इतनी बुरी हालत हो जाती है कि अब वहां बीमारियां बढ़नी शुरू हो गई हैं।

सभापति महोदया, मैं आपके ध्यान में एक और चीज लाऊंगा। हमारे बुंदेलखंड के लोग बाहर वाले से बहुत झगड़ा किए हैं, चाहे ब्रिटिशर्स रहे हो, चाहे मुगल साम्राज्य रहा हो, यह वही देश हैं, जहां पर हमने दक्कन विजय के बाद अकबर की आर्मी को रोक दिया था। हमारे महान राजा वीर सिंह देव जी थे, उन्होंने अयोध्या में कनक भवन बनवाया, मथुरा का मंदिर बनवाया, परंतु अब यह हालत है कि बुंदेलखंड के लोग आपस में ही झगड़ते हैं। हमारे यहां एक-एक पानी के टैंकर्स के ऊपर झगड़ा शुरू हो जाता है। सड़कें इतनी दूर हैं कि अगर एक टैंकर किसी गांव में आ जाए, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। जल के स्रोत इतने दूर रह गए हैं, हमारा क्षेत्र पथरीली है, वाटर लेवल काफी नीचे है। It is quartz and it is granite. You cannot do deep-bore tube well. वहां हम 150, 250 और 300 फुट नीचे चले जाते हैं और आधे ग्रेनाइट की वजह से फेल हो जाते हैं।

ऊपर से अगर आप डीप बोरिंग भी करने लग गए, तो वहां पानी के चांसेज़ इतने पुअर हैं कि इतने पैसे लगाने के बाद वह 99 पर्सेंट अनसक्सेज़फुल रहेगा। मेरे क्षेत्र में तकरीबन 10 हजार से ऊपर हैंडपंप सूखे पड़े हैं। एक माननीय सदस्य आए थे, उन्होंने कुछ पिक्चरें बनाई हैं। वे हैंड पंपों की बात कर रहे थे। वे कहीं भी जाते थे, तो लोग उनको किसी पिक्चर की वजह से हैंड पंप दे देते थे। मैंने कहा कि आप झांसी आ जाइए। आपको जितने हैंड पंप चाहिए, हम आपको गिफ्ट कर देंगे। हमारे यहां पानी का बहुत अभाव है। सारे हैंड पंप सूखे पड़े हुए हैं। …(व्यवधान) यहां लोग 50-50 मिनट बोल रहे हैं।

माननीय सभापति : इसीलिए मैं पहले ही बोल रही हूं।

श्री अनुराग शर्मा: महोदया, मेरा दु:ख-दर्द तो एक बार बयां हो जाने दीजिए।

माननीय सभापति: आपका दु:ख-दर्द हम सबको समझ आ गया है।

SHRI ANURAG SHARMA : This has led to no industries there. Industries will not come to a place like Bundelkhand.

HON. CHAIRPERSON: Why?

SHRI ANURAG SHARMA : They want water but there is no water available. How can you possibly run an industry without water? Today, the Government of India has announced one of its largest packages in that area called the Defence Corridor. We have already got over 2,000 acres of land identified and acquired by the Government of India. This has got to be extended to nearly 2,000 odd hectares. Now, if any industry wants to come there, the first thing it is going to ask for is land. The next they will ask for is water. अगर वहां पानी ही नहीं है, तो इंडस्ट्री कैसे आएगी? माननीय सभापति, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे यहां आने की बात हो रही है और अगर वहां पानी नहीं होगा, तो कैसे चलेगा? This has led to mass migration.

मुझे यहाँ वेस्टर्न कोर्ट में एक कमरा दिया गया है। मैं जब पहली बार वेस्टर्न कोर्ट एनेक्सी में गया, तो मुझसे 15 लोग मिलने आये। वे सब के सब बुंदेलखंड से

थे। वे सब के सब गार्ड्स थे। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे काम कर रहे हैं? उनकी तरफ से बताया गया कि उधर काम कहाँ है। अपने परिवारों को लेकर वे सब यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत से माननीय सदस्य वेस्टर्न कोर्ट में रहते होंगे। आपको जितने भी गार्ड्स वहाँ मिलेंगे, वे सब बुंदेलखंड के हैं। हमारे झाँसी रेलवे स्टेशन से हजारों लोग डेली माइग्रेट करते हैं। गर्मियों के मौसम में वहाँ जगह नहीं मिलती है। 20 से 25 हजार आदमी तक स्टेशन से जाते हैं। कुछ ट्रेनें तो सिर्फ माइग्रेशन के लिए हो गई हैं। वे वहाँ से अपना गाँव छोड़कर नौकरियाँ ढूँढने के लिए दिल्ली, लखनऊ या पंजाब जा रहे हैं। इतने बड़े लेवल पर माइग्रेशन हो रहा है। वे किनको छोड़कर जाते हैं? अपने जानवरों को और बूढ़े माँ-बाप को। उनकी देखभाल करने वाला वहाँ कोई नहीं रहता है। वहाँ पानी का बहुत अभाव है। वे बेचारे पानी नहीं ला पाते हैं। उन्हें उनके पास पानी पहुँचाने के लिए कोई न कोई विशेष प्रबंध करना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सी समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं।

माइग्रेशन की वजह से हमारे बच्चों की एजुकेशन खराब हो रही है। हम बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का आन्दोलन सब जगह छेड़ते हैं, पर बेटी को तो तब पढ़ने को मिलेगा, जब वह बेचारी सुबह पानी लेने के लिए नहीं जाएगी। अगर उस बच्ची को उसके माँ-बाप पानी लेने के लिए भेज देते हैं, तो वह कैसे पढ़ेगी? हर बार यही होता है। The school drop-out rate for young girls in rural Bundelkhand is probably over 45 per cent. They suffer from malnutrition. तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर उस धूप में जाना पड़ता है। बुंदेलखंड के लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं कि जब वहाँ गर्मी पड़ती है, तो वहां रिकार्ड गर्मी पड़ती है। हमारे यहां औसत तापमान, जो हमारे यहां नौतपा कहा जाता है, वह 48 डिग्री रहता है और रात का तापमान 39 डिग्री से नीचे नहीं आता है।

उस भयानक गर्मी में लोग पानी कलैक्ट करने के लिए जाते हैं इसलिए नदी जोड़ने के लिए अभियान बहुत जरूरी है। मुझे डर लग रहा है कि आप घंटी न बजा दें। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहूंगा। हमारी नदियां उतरायण हैं, इनका वॉटरशेड एरिया, 427 किलोमीटर दूर है और दूसरा 610 किलोमीटर दूर है, ये यमुना में मिलती हैं। दोंनों अलग-अलग एमपी के एरिया से

स्टार्ट होती हैं। बेतवा नदी होशंगाबाद जिले से शुरू होती है और केन नदी मध्य प्रदेश के कटनी जिले के पास से निकलती है। यहां औसतन बारिश ग्यारह से बारह सौ मिलिमीटर होती है। हमारे चार सौ पांच सौ मिलिमीटर से दोगुनी बारिश होती है। यहां पर 90 परसेंट तक चार या पांच साल में अच्छी बारिश हो जाती है। इस एरिया में चैक डैम जरूर बने हैं, कुछ बड़े डैम्स भी बने हैं, वह पानी कुछ ही एरिया को सिंचिंत कर पाता है।

यह स्कीम सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा कंसीव की गई थी। यह उनका ही आइडिया था। उनकी सोच वहां से शुरू होती थी जहां से लोगों की सोच अक्सर खत्म हो जाती है। उन्होंने इस देश के लिए इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का इतना बड़ा सपना देखा था, New marvels of engineering can be executed. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक विशेष रूप से कमेटी गठित की थी। नेशनल वॉटर डेवलपमेंट एजेंसी ने एक कम्प्रिहेन्सिव रिपोर्ट भी बनाई थी, इसको फेज वन और फेज टू में किया गया था। इसके अलावा, दोनों सरकारें मान गई थीं, दोनों सरकारों में विलय भी हो गया था। शुरू में कुछ परेशानियां जरूर रही थीं कि किसको कितना पानी मिलेगा, लेकिन बाद में एमओयू भी साइन हो गया था। एनजीटी से भी एप्रूव्ड हो गया था। वाइल्ड लाइफ बोर्ड से कुछ ऑब्जेक्शन्स आए थे, वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने इसके लिए कहा था, वहां एक पन्ना टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जमीन दे दी जाएगी। इसके लिए सरकार मान गई थी। वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व छोटा नहीं किया जाएगा और इसे बड़ा कर दिया जाएगा। ये सारे ऑब्जेक्शन्स क्लियर हो चुके हैं। जब ये सारे ऑब्जेक्शन्स क्लीयर हो गए थे तब भी इस पर कार्य शुरू नहीं हो पाया है। आज यह देश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट होगा क्योंकि यह टेक्नीकली प्रूव कर सकेगा We are capable of linking our rivers and this is the only project where I think the Government of India has done a detailed and comprehensive study to clear this. Not only will it revive water, it will also be able to generate solar power. They are planning to cover the canal and it will generate 140 megawatts of hydel power and 27 or 30 megawatts of solar energy.

Nearly 9 lakh hectares of land could be annually irrigated through this project; 4843 million cubic metre of water including drinking water supply will be generated.

The project was envisaged in two phases; one costs about Rs.14,000 crore and the other about Rs.21,000 crore.

I would again request the Mantri ji to look into this project.This has a positive rate of return. It is not only socially good for the country, but also economically beneficial for the country. It probably has an IRR, if I am right, of 10.95 per cent, which for a social engineering project like this, will be a boon.

मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप इस विनती पर थोड़ा सा गौर करें और देश में पहला प्रोजेक्ट बनाने की व्यवस्था करें।

माननीय सभापति श्रीमती : माननीय मंत्री जी बैठे हैं, प्वाइंट्स ले रहे हैं।

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): माननीय सदस्य और अन्य सदस्यों ने जो बात कही हैं, जब चर्चा समाप्त होगी तो निश्चित रूप से सारे विषयों पर विस्तार से बात करूंगा। माननीय सदस्य ने बुंदेलखंड की विशेष परिस्थितियों के बारे में बात की है और बुंदेलखंड में जो हालात है, उस दर्द को आपके माध्यम से सदन और देश के सामने रखा है।

माननीय सदस्य ने बुंदेलखंड के राजाओं की वीरता और इतिहास की चर्चा की। उन्होंने इसकी भी चर्चा की कि किस तरह से मंदिरों का निर्माण किया, तालाबों का निर्माण किया। तालाबों की जो वर्तमान स्थिति है, इतिहास साक्षी है, इस तरह के रिकॉर्ड मौजूद हैं कि 9,000 तालाब चन्देल राजाओं ने 1000 बीसी से

600 बीसी तक बनाए थे। इन तालाबों में से आज केवल 250 तालाब बचे हैं और ऐसी परिस्थिति में 2500 को रिस्टोर किया जा सकता है।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने जलशक्ति अभियान प्रारंभ किया है, उसका मूल यही है। उन्होंने सभी सांसदों से अपेक्षा की है और मैंने भी सबको पत्र लिखा है कि सब अपने क्षेत्र में वाटर लीडर की तरह काम करें। अभी यह अभियान चल रहा है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा और बुंदेलखंड और अन्य क्षेत्रों से जो सदस्य आते हैं, सब इस अभियान के साथ जुड़ें और अपने क्षेत्र में इन सब विषयों को देखें। उन 250 तालाबों में जहां काम हुआ है, वहां बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। यदि ऐसा करेंगे तो केन-बेतवा लिंक एक तरफ है, आप अपने क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी राहत दे सकेंगे।

माननीय सभापति: अनुराग जी, आप पर्सनली मंत्री जी से मिल लीजिए, जो स्कीम है उसे अपने क्षेत्र में ले जाइए। यह स्कीम पूरे देश के लिए है, लेकिन बुंदेलखंड की जो समस्या है, वैसी समस्या समस्या बाकी क्षेत्रों की नहीं है।

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): माननीय सभापति जी, आपने मुझे कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा सामाजिक संकल्प, जो बुंदेलखंड की जल की स्थिति और अन्ना प्रथा से संबंधित है, पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि इस पर बोलूं या न बोलूं क्योंकि सवाल अन्ना प्रथा की व्यवस्था और जल का संकट का है। जल संकट तो आज देश में बहुत विकराल रूप में सामने खड़ा हुआ है। अन्ना प्रथा का विषय सीधे मेरे लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा है। कौशाम्बी लोकसभा की अगर बात की जाए, तो इसके पूर्व में पूर्वांचल है, पश्चिम में कानपुर है, उत्तर में अवध क्षेत्र है और दक्षिण का भाग बुंदेलखंड से लगा हुआ है। यहां यमुना नदी है, जो हमें आपस में बांटती है। एक तरफ बुंदेलखंड और दूसरी तरफ दुआबा है।

जब इस बिल पर चर्चा शुरू हुई तो इसका मुख्य विषय था कि अन्ना प्रथा में लोग पशुओं को छोड़ते हैं। मैंने इस पर ध्यान दिया। जब मैंने उस पर ध्यान दिया तो यह समस्या अब केवल बुंदेलखंड तक नहीं है। अन्ना पशुओं को लेकर बुंदेलखंड की समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि अब लोग वहां से उससे मुक्ति पाने के लिए अपने सभी जानवरों को यमुना से पार करके मेरी लोक सभा क्षेत्र में भेज रहे हैं। यह एक बड़ा संकट है। मेरे बगल के, बांदा के माननीय सांसद जी हैं। निश्चित रूप से यह समस्या केवल बुंदलेखंड की ही नहीं है, बल्कि आने वाले समय में जिस तरह से भूजल स्तर गिर रहा है, उसके कारण ये समस्या धीरे-धीरे बढ़ेगी और विकराल होती जाएगी। माननीय प्रधान मंत्री जी की पहल पर देश के 1592 ब्लॉकों को चिह्नित किया गया है, जिनमें 256 जिले हैं, जो इस जल संकट से जूझ रहे हैं, इसमें मेरा भी जनपद है। मेरी लोक सभा में 12 ब्लॉक्स हैं, इनमें 10 ब्लॉक डार्क जोन में हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में स्थिति और भी खराब होगी।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसको ध्यान में रखते हुए जिस तरह से जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है, उससे स्पष्ट है कि माननीय प्रधान मंत्री जी को इस विषय का संज्ञान भी है और चिन्ता भी है। मैं बुंदेलखंड के किसानों के साथ अपना समर्थन व्यक्त करते हुए इतना कहना चाहूंगा कि देश की सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों की आय दोगुनी हो, किसान की आय बढ़े और बुंदेलखंड में वे सारी चीजें विद्यमान हैं। इसका बहुत ही गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास है। यह वीरों की भूमि है, जोत भी बड़ी है। सब कुछ होने के बावजूद आज बुंदेलखंड के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। उसके मूल में जो कारण है, वह कारण कुछ और नहीं केवल जल है। माननीय प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो, इसके लिए देश भर के किसानों को नीम कोटेड यूरिया समय पर उपलब्ध करा रहे हैं, उनकी आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध करा रहे हैं, जितनी उनकी आवश्यकता है, उनको मिल रही है। लेकिन, बुंदेलखंड का किसान बेचारा क्या करे, वह फर्टिलाइजर लेकर क्या करेगा, क्योंकि पानी ही नहीं है तो वह खेती कहां से करेगा। माननीय प्रधान मंत्री जी किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगतार एमएसपी बढ़ा रहे हैं। लेकिन

एमएसपी का बुंदेलखंड के किसानों को तब मिलेगा, जब वे फसल पैदा करेंगे। उनकी फसल दिनोंदिन घटती जा रही है तो वे किसानी नहीं करेंगे। जब किसान अन्न पैदा ही नहीं करेगा तो कहां से उसे फसल का लाभ मिलेगा। माननीय प्रधान मंत्री जी किसानों की आय को लेकर चिंतित है। वर्ष 2014 में जब सरकार बनी तो माननीय प्रधान मंत्री ने देश भर में सॉयल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की । उस योजना का लाभ देश के किसानों को मिल रहा है, लेकिन बुंदेलखंड के किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वे चाहकर भी नहीं ले सकते है, क्योंकि जो मूल आवश्यकता पानी है, वह उनको नहीं मिल रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बीज से लेकर बाजार तक की व्यवस्था की है, उसका लाभ भी बुंदेलखंड के किसानों को नहीं मिल रहा है। चाहे फसल बीमा योजना हो, जब वे फसल पैदा नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे तो बीमा का लाभ उन्हें कहां से मिलेगा। निश्चित रूप से बुंदेलखंड के किसानों की मूल समस्या जल है और यह समस्या अब केवल बुंदेलखंड की नहीं है। आज पूरे देश में इसका संकट है। मुझे लगता है कि ऐसे ही समय को देखते हुए रहिमन ने एक बार लिखा था-

"रहिमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून,

पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून।"

जब पानी ही नहीं है तो न मोती होगा, न मानुष बचेगा और न ही चून इसलिए पानी की आवश्यकता जितनी है, उतनी ही बुंदेलखण्ड पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आने वाले समय में जल संकट को समझते हुए नदियों की शुरुआत की थी। ऐसा कार्य करने वाले वह देश के पहले प्रधान मंत्री थे और इसको समय पर किया जाता, इसकी समय पर शुरुआत होती तो मुझको लगता है कि आज बुंदेलखण्ड की जो समस्या विकराल हो गई है, उससे हम लोग बच सकते थे या उसमें थोड़ी कमी ला सकते थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों की अदूरदर्शिता के कारण आज किसान वहां पर केवल खेती के पानी के लिए ही नहीं, बल्कि उनको पीने के लिए भी शुद्ध जल मिल नहीं पा रहा है। निश्चित रूप से बुंदेलखण्ड के

एक साथी ने कहा कि 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' बेटी को जब घरके काम से मुक्ति मिलेगी, समय मिलेगा तभी तो पढ़ाई करेगी। सबसे ज्यादा समय तो उनका पानी ले जाने में खर्च हो जाता है। देश की एक नहीं अनेक योजनाएं हो, चाहे महिला सशक्तीकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या किसानों की बात हो ये सब जल पर निर्भर करती हैं। बुंदेलखण्ड के लिए कहा जाए तो पानी की जितनी आवश्यकता है, जितने में जीवन चल सकता है, कम से कम उतने पानी की तो व्यवस्था की जानी चाहिए। निश्चित रूप से सरकार इसके लिए चिंतित है। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने अपने पहले कार्यकाल में स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान को एक मिशन मोड में लेकर देश में अभियान चलाया था, जिसके कारण आज देश स्वच्छता की ओर बढ़ा है। चारों ओर देश में स्वच्छता दिखाई पड़ती है।

17.00 hrs

देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही जल की गंभीरता को महसूस करते हुए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया और जल शक्ति मंत्रालय का नेतृत्व भी एक ऐसे प्रदेश के नेता को दिया, जो तेज तर्रार और युवा हैं, जिनके प्रदेश का पूरा जीवन जल संकट से जूझता रहा। इस बात के लिए मैं शर्मा जी को फिर जोड़ूंगा कि राजस्थान में जितनी चर्चा पानी के संकट की है, उससे ज्यादा पानी का संकट बुंदेलखण्ड में है। आज वहां गांव के गांव खाली हैं। वहां पर हमारे क्षेत्र से लगा हुए एक क्षेत्र है, जहां न तो रहने के लिए लोग बचे हैं और न ही पशु बचे हैं और जो पशु बचे भी हैं, वे पशु भी बेचारे चारा और पानी की तलाश में पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। सड़कों पर घूम रहे हैं। उनसे एक नहीं अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आज वे लोगों के बीच में झगड़े का कारण बन रहे हैं, रोड पर आ जाए तो एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं, तो ऐसी एक नहीं अनेक समस्याएं हैं। निश्चित रूप से यह सामाजिक संकल्प जो लाया गया है, उस पर सरकार ध्यान देगी, लेकिन यह काम सरकार ही करे यह संभव नहीं है, क्योंकि जल किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता, किसी टेक्नोलॉजी से नहीं बन सकता, जल तो केवल और केवल उसके सदुपयोग से और उसका संरक्षण करके बचाया जा सकता है।

निश्चित रूप से मंत्री जी ने इस संबंध में सभी सांसदों को पत्र भी लिखा है और उनकी यह अपेक्षा है कि सभी सांसद और केवल सांसद ही नहीं, देश का बच्चा-बच्चा, देश का हर जागरूक नागरिक, देश के हर सम्भ्रांत नागरिक, सभी को इस चिन्ता होनी चाहिए। वे जब तक इसमें वाटर लीडर के रूप में काम नहीं करेंगे, इस जल संकट का समाधान नहीं हो सकता है। मैंने भी सांसद बनने के बाद कुछ संकल्प लिए कि इसे कैसे किया जाए। मेरे लोक सभा क्षेत्र में आठ ब्लॉक्स डार्क जोन में हैं। आप कल्पना कीजिए कि आठ ब्लॉक्स डार्क जोन में हों तो वहां स्थिति कितनी भयावह होगी। लोगों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि कौशाम्बी लोक सभा क्षेत्र मां गंगा और मां यमुना की अन्तर्वेदी में है, जिसके कारण सिंचाई के लिए कुछ पानी गंगा की कैनाल से मिल जाता है और कुछ यमुना की कैनाल से मिल जाता है, लेकिन उनकी भी एक सीमा है। आने वाले समय में जिस तरह से डिमाण्ड बढ़ रही है, वे उसे पूरा नहीं कर पाएंगे।

मैंने अपने लोक सभा क्षेत्र में एक संकल्प लिया और यह तय किया कि जितनी भी बरसाती नदियां हैं, उन सब जितने चेक डैम बनाने की जरूरत है, उसके लिए मैंने संबंधित अधिकारियों के साथ पहली बैठक में ही रिपोर्ट बनाने और योजना बनाने के लिए कहा दिया कि आप इसकी रिपोर्ट बनाइए और एक योजना बनाइए। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो चाहे मनरेगा से पैसा लेने की जरूरत होगी, चाहे सांसद निधि से पैसा देने की जरूरत पड़ेगी या जन-भागीदारी के माध्यम से हम उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जल को संरक्षित किए बिना हम इस कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं। जल के विषय में देखा जाए तो भारत का बहुत ही गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास रहा है। भारत की सभी सभ्यताओं का जन्म और विकास नदियों के किनारे हुआ, लेकिन जागरूकता के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, सरकार के प्रयास के अभाव में और जिस तरह से दिनों-दिन हमने जल का दोहन किया, उसके हिसाब से हमने जल का संरक्षण नहीं किया। हमने जल का दोहन ज्यादा किया गया और संरक्षण कम किया, जिसके कारण आज जल संकट देश के सामने खड़ा है।

मैंने एक सामाजिक संकल्प मूव किया है। वैसे जल राज्य का विषय है और केन्द्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन मैं जो संकल्प ला रहा हूं, उसमें मैंने सरकार से अनुरोध किया है कि जल को केन्द्र सूची में रखा जाए, नहीं तो कम से कम इसे समवर्ती सूची में रखा जाए। जिस समय देश में जल का संकट नहीं था, उस समय यह बात समझ में आती थी कि इसे राज्य पर छोड़ा जाए, लेकिन अब जल संकट केवल राज्य ही नहीं, राष्ट्रव्यापी हो गया है। कई इतिहासकार और कई जानकार कहते हैं कि अगर अगला विश्वयुद्ध दुनिया में होगा तो वह जल के लिए होगा। निश्चित रूप से केवल सरकार पर निर्भर रहकर इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, इसमें हमें अपने स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा, समाज को जागरूक करना पड़ेगा। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने जब इसका बीड़ा उठाया है और जब इन्होंने इसे अपने हाथ में लिया है तो आज सरकार की इतनी विश्वसनीयता है कि यह संभव है।

मैंने पिछले भाषण में एक बात कही थी कि मोदी है तो मुमकिन है, तब लोग हंस रहे थे, लेकिन आज सभी नेता, सभी वक्ता इस बात को कहते हैं कि देश में अगर मोदी है तो मुमकिन है। अगर देश के यशस्वी प्रधान मंत्री ने इसका बीड़ा उठाया है तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय में जल संकट से केवल बुंदेलखण्ड को ही मुक्त नहीं करेंगे, बल्कि पूरे देश को भी मुक्त करेंगे। हमें देश को जल मुक्त नहीं करना है, जल युक्त करना है। इस देश में पर्याप्त जल है, जल की कमी नहीं है। हमारे पास जल के एक नहीं, अनेक स्रोत हैं। वर्षा के कारण जल हमें पर्यापत मात्रा में मिलता है, हमारी छोटी-बड़ी नदियां हैं, जिनके माध्यम से हमें जल मिलता है, लेकिन आवश्यकता है उनका संरक्षण करने की, आवश्यकता है उसका नए ढंग से प्रबंधन करने की। गडकरी जी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि 5 एमजीडी या 10 एमजीडी जल के लिए हमारी प्रदेश सरकारें आपस में लड़ती रहती हैं और उससे कई हजार गुना जल हम लोग समुद्र में जाने देते हैं।

जहां नदियां समुद्र में मिलती हैं, अगर हम लोग वहां समुद्र के मुहाने पर बांध बना कर नदियों के जल को पुन: प्रवाह के लिए प्रयास करें तो निश्चित रूप से देश को जल संकट से ही नहीं उबारेंगे, बल्कि आने वाले समय में यह केवल

सोशल इंजीनियरिंग ही साबित होगा, यह बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स भी है। इससे बहुत बड़ा लाभ देश को हो सकता है। जब दुनिया में पानी के लिए हाहाकार मचेगा, तब हम पानी की बहुत बड़ी ब्रांडिंग कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के विधान सभा में एक बार बोला गया कि जब इस देश में डिब्बाबंद, बोतलबंद पानी की शुरुआत हुई, तो वहां पर किसी ने कहा था कि दूध से महंगा पानी है। आज यह हालत है कि बोतलबंद पानी दूध से भी महंगा होता जा रहा है। आने वाले समय में इसकी स्थिति और खराब होगी।

सभापति महोदया, हम लोग यहां प्राइवेट मैम्बर बिल पर चर्चा करने के लिए रुके हुए हैं कि हमें पर्याप्त अवसर मिलेगा, पर्याप्त बात रखी जाएगी, क्योंकि यह संकट अब केवल बुंदेलखंड का संकट नहीं है, यह संकट पूरे देश का हो चुका है। मैं आपका पड़ोसी हूं तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड के बाद मेरा क्षेत्र ही प्रभावित होने वाला है। इसलिए मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपके साथ अपने को जोड़ने के लिए भी खड़ा हूं और बुंदेलखंड की जो संवेदना है, वेदना है, जितनी वेदना और संवेदना के साथ आपने बुंदेलखंड की बात को रखा है, निश्चित रूप से यह पिछले सैंकड़ों साल से बुंदेलखंड की वेदना को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। आज देश में कहीं मजदूर मिलेंगे तो वे दो ही जगह के होंगे। वे बुंदेलखंड के होंगे या पूर्वांचाल के होंगे। इत्तेफाक देखा जाए तो चाहे बुंदेलखंड हो या पूर्वांचल हो, इनका बहुत गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास रहा है। ये बहुत समृद्ध प्रदेश रहे हैं, लेकिन आज यहां के लोग छोटी-छोटी मजदूरी के लिए पलायन करने के लिए मजबूर हैं। छोटे-छोटे कामों के लिए अपने मां-बाप को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। निश्चित रूप से यह बहुत ही संवेदनशील विषय है। इसको केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। हम लोगों को इसमें सरकार की अनेक योजनाएं का उपयोग उसको बढ़ावा देकर, भी कुछ समस्याओं को कम कर सकते हैं। चाहे वह स्प्रिंकल सिंचाई का माध्यम हो, जिसमें जितनी पानी की जरूरत है, ऐसे फसलों को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिसकी वजह से पानी की बचत होगी।

साथ ही साथ सॉइल हेल्थ कार्ड, जो भारत सरकार, देश के प्रधान मंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, उसको भी बड़े पैमाने पर जागरूक किया जाए, लागू

किया जाए, तो उससे भी पानी की बचत होगी।

मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूं। हम लोग पीने के लिए जो पानी हैंड पम्प लगवाते हैं, वह हमारे यहां 30 हजार रुपये से 40 हजार रुपये में लग जाता है, लेकिन बुंदेलखंड में वह हैंड पंप एक से डेढ़ लाख में भी नहीं लग पाता है। एक से डेढ़ लाख रुपये लगाने के बावजूद, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह हैंड पम्प सफल होगा, वहां पानी मिलेगा। यह स्थिति धीरे-धीरे बढ़ रही है। हम लोगों के यहां भी जल स्तर लगातार गिर रहा है।

सभापति महोदया, मैं सरकार को बधाई भी दूंगा कि वह बुंदेलखंड पर लगातार चिंता कर रही है। चाहे बुंदेलखंड के समग्र विकास की बात हो, बुंदेलखंड के पीने के पानी की बात हो या सिंचाई की बात हो। वह कैसे उपलब्ध हो, माननीय प्रधान मंत्री जी इसको लेकर चिंतीत हैं। 15 हजार करोड़ रुपये का एक पैकेज बुंदेलखंड को दिया गया, जिससे आने वाले समय में वहां जल संकट के समाधान का रास्ता निकलेगा। बुंदेलखंड में जिस तरह से डिफेंस कॉरिडोर माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रयास से शुरू की गई है, वहां पर्याप्त जमीन है।

वहां उद्योग की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं। जिस डिफेंस कोरिडोर की शुरूआत की गई है, वह बुंदेलखंड तक आ रहा है। उसकी वजह से भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बुंदेलखंड में इंडस्ट्री शुरू करने के लिए भी जल की आवश्यकता है। माननीय जल मंत्री सदन में हैं, इन्होंने योजना की शुरूआत की है। सबसे पहले बुंदेलखंड में केन और बेतवा नदी को जोड़ना चाहिए। यह कोई नई योजना नहीं है। अटल जी ने 37 परियोजनाओं की शुरूआत की थी। इन योजनाओं में यह योजना भी थी लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। पर्यावरणविदों द्वारा लगातार सवाल खड़ा किया गया कि इससे इतने लाख पौधे खत्म हो जाएंगे, हमारा फारेस्ट रेंजर खत्म हो जाएगा। उसके समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था की है और मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि केन और बेतवा नदी को जोड़ने में कोई संकट है। एनजीटी से भी क्लीयरेंस मिली हुई है। सरकारों के बीच में भी आम सहमति है। सरकारों के बीच में जल बंटवारे को लेकर समझौता है। यदि इस काम को शुरू करते हैं तो

अटल जी ने नदियों को जोड़ने का जो सपना देखा था, उसके माध्यम से हम पुनः बुंदेलखंड को स्थापित कर पाएंगे और साथ ही साथ देश और दुनिया के सामने हम एक मॉडल भी स्थापित कर पाएंगे कि एक सफल रिवर लिंकिंग कैसे होता है।

महोदया, मैं फिर यही बात कहूंगा कि यदि मोदी जी हैं, तो मुमकिन है। अगर मोदी जी न होते, तो शायद ये काम संभव ही नहीं होते, क्योंकि इतने लम्बे समय से जल का संकट देश में है। देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, जहां जल का संकट न हो चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, बहुत प्रदेशों में जल का संकट है, लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया। मोदी जी के विजन से यह चीज सफल होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जब ये नदियां आपस में जुड़ेंगी, तो आने वाले समय में जल के संकट का समाधान होगा और बुंदेलखंड के लोगों को पुनः स्थापित करने का अवसर मिलेगा और देश की नदियों को जोड़ने का एक बढ़िया उदाहरण हम पेश कर पाएंगे, यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री आर. के. सिंह पटेल (**बांदा**): सभापति महोदया, आपने मुझे कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चन्देल द्वारा प्रस्तुत संकल्प बुंदेलखंड में छुट्टा गोवंश, जिसे अन्न प्रथा कह रहे हैं और जल संकट पर लाया गा है, उस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं बुंदेलखंड के बांदा की धरती से चुनकर आया हूं। यह धरती भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या से चलकर बारह साल तक वनवास में रहे। भगवान राम ने माता सीता के साथ और भ्राता लक्ष्मण जी के साथ बिंद बुंदेलखंड प्रांत में विचरण करने का काम किया, मैं उस धरती से चुनकर आया हूं।

बुंदेलखंड क्षेत्र में अलग-अलग तरह की मिट्टी है और अलग-अलग तरह की वाणी है। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का मिलाजुला क्षेत्र है। वहां की मिट्टी, वहां का पानी, वहां की वाणी, वहां की जलवायु बहुत स्वच्छ है। वहां पन्ना हीरा पाया जाता है। तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर वहां है। वहां कांतानाथ जी की तपोस्थली है। वहां ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। वह परिक्षेत्र जहां वीरांगना लक्ष्मी बाई जैसी महान विभूति का जन्म हुआ।

"खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी,

बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी।"

वह धरती है बुंदेलखंड की। आज वह आल्हा-ऊदल की धरती बुंदेलखंड है।

खट-खट, खट-खट तेगा बोलै,

बाजै छपक-छपक तलवार।

वहाँ की जो परम्परा रही है, जिन्होंने अपना इतिहास बनाया है और वह राजा छत्रसाल की कर्मभूमि रही है।

इत यमुना उत नर्मदा, इत चम्बल उत टौंस,

छत्रसाल से लड़न को ना काहु में धौंस।

वह बुंदेलखंड क्षेत्र, जहाँ के राजा छत्रसाल रहे हैं, वहाँ के पन्ना में आज भी हीरा पाया जाता है। वहाँ मराठाओं का भी साम्राज्य रहा है। मराठाओं द्वारा बनाए गए बहुत-से ताल-पोखरिया के पद-चिह्न आज भी वहाँ विद्यमान हैं। वहाँ चंदेल कालीन किले, मंदिर, तालाब हैं और बहुत-से सांस्कृतिक चिह्न विद्यमान हैं। खजुराहो मंदिर उस बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्यमान है। आज वहाँ के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं, पानी के अभाव में जीने के लिए मजबूर हैं। अपनी भूख-प्यास मिटाने के लिए पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। आज वहाँ विकट समस्याएँ खड़ी हो रही हैं।

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): I have a point of order. I think there is no quorum. …(*Interruptions*)

श्री आर. के. सिंह पटेल: बुंदेलखंड में एक कहावत है- "कोस-कोस में पानी बदले और पाँच कोस में वाणी, बुंदेलों की यही कहानी।" बुंदेलखंड में कोस-कोस पर पानी बदलता है। कहीं पर 500 फीट नीचे पानी है, तो कहीं सौ फीट पर है, कहीं पर 50 फीट पर भी है। बुंदेलखंड में एक तरफ पंजाब जैसा क्षेत्र है, एक तरफ गुजरात जैसा क्षेत्र है, एक तरफ हिमाचल जैसा क्षेत्र है, तो एक तरफ माँ कामाख्या की गौहाटी जैसा क्षेत्र है, एक तरफ कश्मीर जैसा क्षेत्र है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह बुंदेलखंड क्षेत्र आज पूरी तरह से विश्व के युग पुरुष, भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अलग से जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके और जल संरक्षण करके 20 जून को प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक अभियान चलाकर और गाँव-गाँव में चौपाल लगाकर जल संरक्षण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके माननीय प्रधान मंत्री जी एक सराहनीय कार्य किया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारी इस समस्या का निदान मिलेगा। मुझे यह पूरा भरोसा है।

गाँव का पानी गाँव में, खेत का पानी खेत में संचय करने की पहल की जा रही है। आज से कई वर्ष पूर्व तालाबों को भरने के लिए आपस में लोगों की एक समिति बनाई जाती थी। उस समिति के माध्यम से, मेरे बचपन के समय में, मुझे याद है, मैं गाँव के एक किसान का बेटा हूँ, मैं खेती-किसानी करता आया हूँ और आज भी करता हूँ। उस समय जब बरसात का पानी बरसता था, तो उस पानी को संचय करने के लिए हम फावड़े उठाते थे, जो बड़े-बड़े जमींदार और नम्बरदार हुआ करते थे, जो फावड़ा नहीं चला सकते थे, वे किसी श्रमिक को भेजकर उसको मजदूरी देकर यह कराते थे। खेतों का पानी बहकर नालों, नदियों, यमुना से समुद्र में जाता था, उन तालाबों के पानी को हम संचित करने का काम करते थे। आज यह परम्परा समाप्त हो गई है। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे, आदरणीय शर्मा जी कह रहे थे, बहुत-से तालाब आज भी विद्यमान हैं।

अब उन तालाबों पर संचय करने की दिशा बदल गई है। वे नाले जो तालाबों पर आते थे, वे आज दूसरी तरफ डायवर्ट हो गए हैं और मैं अपनी भाषा में कह दूं तो बम खटाखट हो गए हैं। बम खटा का मतलब है कि सूखे पड़े हैं। हमारे बुन्देलखण्ड में कहा जाता है कि पानी बिना जो सूखा पड़ा है, वहां बम खटाखट। तालाब सूखे पड़े हैं और बरसात का पानी किनारों से निकलकर नालों द्वारा नदियों में जा रहा है। इसके लिए गांव में फिर से माननीय मंत्री जी ने जागृति पैदा करने का अभियान चलाया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि मंत्री जी ने गांव-गांव में इस अभियान को चलाकर उन तालाबों को भरे जाने की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, बुन्देलखण्ड की पानी की जो विकराल समस्या है और इस पानी का संचय करने के लिए केन बेतवा गठजोड़ की उस समय हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरुआत की थी, लेकिन बीच की सरकरों ने इस योजना पर कार्य नहीं किया। आज भी वह समस्या है। केन बेतवा से नदियों के गठजोड़ की स्वीकृति प्रदान होने के बाद काम हुआ होता और बजट फण्डिंग की गई होती तो आज काफी कुछ काम हो गया होता। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पिछले पांच साल की सरकार में उन्होंने इस कार्य योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसमें जो दिक्कतें थीं, उनके लिए बजट देकर, उनको हल करके उसकी शुरुआत करने का काम इस सरकार ने किया है।

महोदय, नदियों से नहरें निकालकर ताल, पोखरों तक छोटी-छोटी पहाड़ी नदियां हैं, बरसाती नदियां हैं। बड़ी नदियों को तो हम लिंक कर रहे हैं, लेकिन छोटी-छोटी जो बरसाती नदियां हैं, उनको नहीं। मेरे क्षेत्र के बांदा और चित्रकूट में लगभग 25-30 छोटे-बड़े बंधे और बंधियां हैं। उन छोटी-बड़ी बंधियों को भरने के लिए उनको छोटी नदियों से लिंक करने की आवश्यकता है। जब बरसात का पानी आता है तो पानी उन नदियों और नालों से निकलकर बाहर बह जाता है और बंधे खाली रह जाते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव है कि उन बंधियों को भरा जाना चाहिए।

हमारे यहां पैसुनी नदी है, जो मां सती अनुसुइया के वरदान निकाली गई थी। "माता सती अनुसुइया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बनकर के लालना"। वह माता सती अनुसुइया का क्षेत्र है और वहां से पेसुनी नदी की अविरल धारा बहती रही है। आज वह पैसुनी की अविरल धारा बंद हो गई है। पूरे क्षेत्र के लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और जल स्तर नीचे जा रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जो हमारी तमाम नदियां हैं, उन नदियों जैसे पेसुनी नदी है, गुंता नदी है, ओहन नदी है, बागेन नदी है, केन नदी है, इनको केनबेतवा गठजोड़ से लिंक करने की जरूरत है। अगर हम इनको जोड़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर अगर एक क्षेत्र में बाढ़ आती है, जैसे मध्य प्रदेश के आदरणीय पटेल जी बैठे हैं, यदि उनके क्षेत्र में पानी बरसता है तो हम उस पानी को डायवर्ट करके चित्रकूट, प्रयागराज तक की धरती तक जहां मेरा क्षेत्र जुड़ा हुआ है, हम वहां तक पानी को ले जा सकते हैं। इसलिए इनको आपस में लिंक करने की आवश्यकता है और इनको भरे जाने की आवश्यकता है। हमारा जो बांदा क्षेत्र है, वहां से केन नदी बहती है। केन नदी में बैराज बनाने की आवश्यकता है। बांदा में पीने के पानी के लिए बड़ी दिक्कत होती है। बांदा में हमारा कमिश्नरी मुख्यालय है और चित्रकूट धाम मंडल का मुख्यालय है। बांदा में पानी की विकराल समस्या है। वहां पीने के पानी और सिंचाई के पानी की समस्या है। सिंचाई के लिए केन नदी से एक केन नहर निकाली गई थी। वहां मध्य प्रदेश की सीमा से रंगावा और बरियारपुर बांध निकाले गए थे। आज रंगवा और बरियापुर बांध पूरी तरह सिल्ट से भर गए हैं। उनकी क्षमता बहुत कम हो गई है। पहले पूरे बांदा जिले को केन नदी से सिंचित करने का काम करते थे। केन नदी से जो नहर केनमाइनर नदी निकाली गई थी, वह माइनर ध्वस्त और जर्जर पड़ी है। उनमें पानी नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश की सीमा से उत्तर प्रदेश में पानी आता था। वहां जल बंटवारे की जो संधि है, उस हिसाब से जो पानी आता है, उससे बांदा जिले के लिए सिंचाई के लिए पानी पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि हमारी केन नदी पर एक बैराज बनाये जाने की आवश्यकता है। बांदा में एक बैराज बना दें तो उस बैराज से हमारा जल स्तर बढ़ेगा। मेरा माननीय मंत्री जी अनुरोध है कि उन बैराजों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया जाए, क्योंकि ये नदियां पहाड़ों से

निकलने वाली नदियां हैं। अगर इन्हें पूरी तरह से बंद करके बांध बना देंगे तो सिल्ट भर जाएगी। अगर इनमें सिल्ट भर जाएगी तो धीरे-धीरे नदियों की क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि बैराज इस तरह से बनाया जाए कि जब बरसात का पानी बाढ़ से आता है तो उस बाढ़ के पानी के लिए बीच से ऐसे फाटक लगाया जाए, ताकि वह सिल्ट बह जाए।

जैसे ही बाढ़ थोड़ा रुकती है, तो फिर से उसके फाटक को बंद कर दिया जाए, जिससे हमारे बैराज सक्सेस होंगे। इस तरह से बांदा में केन नदी पर बैराज बनाने की जरूरत है। बागिन नदी जो बदोसा, बांदा के बगल से जाती है, उसको केन से जोड़ने की आवश्यकता है। बदोसा के पास बाघिन नदी पर बैराज बनाने की आवश्यकता है।

माननीय मंत्री जी, बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को पानी देने की योजना है। इस परियोजना से 50 प्रतिशत पानी मध्य प्रदेश को, 25 प्रतिशत बिहार को और 25 प्रतिशत उत्तर प्रदेश को देने की योजना है। यह परियोजना बहुत लम्बे समय से लंबित थी। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री श्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि पिछले लोक सभा चुनाव से पहले उन्होंने इसकी शुरुआत करके इसका लोकार्पण करने का काम किया है, जिससे हमारे इस पूरे क्षेत्र को लाभ मिल सकता है। अत: मेरा आपके माध्यम से यह आग्रह है कि बाण सागर परियोजना को सतना और रीवां, जो मेरे बगल के क्षेत्र हैं, वहां तक इस परियोजना की नहरें आई हैं। प्रयागराज के मेजा, करछना क्षेत्र को उसमें शामिल किया गया है। मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों को उसमें शामिल किया गया है। मेरा आपसे आग्रह है कि चित्रकूट, बांदा का जो क्षेत्र है, बाण सागर परियोजना की जो नहरें हैं, वे वहां से होकर जाएं। चूंकि ऊपर से पहाड़ हैं, मध्य प्रदेश के हिस्से से सतना, रीवां से ऊपर का घाटीनुमा पहाड़ हमारे क्षेत्र की तरफ आता है, नहरें ढालनुमा हमारी तरफ चली आएंगी। इनकी टेल हमारे यहां यमुना नदी में आ जाएगा। अत: उनको हमारे यहां यमुना नदी तक टेल से जोड़ दिया जाए, तो जो हमारे छोटे-बड़े बंधे हैं, बाण सागर परियोजना से जब एक्स्ट्रा पानी होगा और जब वहां बरसात होगी तो बरसात का पानी भी आएगा। अत: मुझे

लगता है कि आपके यहां से बांध जो परियोजनाएं आती हैं, उनसे निश्चिचत तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और बांदा जिले के छोटे-बड़े बांधों को लिंक बनाकर जोड़ने से पानी की समस्या का निदान हो सकता है।

महोदया, बाण सागर परियोजना से चित्रकूट और बांदा जिले को जोड़ने की मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको शामिल करने का काम किया जाए जिससे हमारे चित्रकूट के पाठा की धरती जो प्यासी है, वह सिंचित हो सकती है, वहां की प्यास बुझ सकती है। सन् 1970 के करीब हमारे पाठा में एशिया की सबसे बड़ी परियोजना बनाई गई थी। हमारी जो परुष्णी नदी है, उस नदी से लिफ्ट करके पाठा पर एक जल योजना बनाई गई थी और पाठा क्षेत्र के पठारी भाग के गांव को पीने का पानी मिलता था, लेकिन आज परियोजना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है।

महोदया, मैं प्रधान मंत्री जी को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पेयजल समस्या को हल करने के लिए बुन्देलखण्ड के लिए विशेष रूप से 9 हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। प्रत्येक घर तक टोटी से पानी देकर के पाइप लाइन से पानी देकर प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य आदरणीय प्रधान मंत्री जी का है, हमारी सरकार का है और जल शक्ति मंत्री जी का है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि यह हमारे क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होगा। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि इन चीजों को करने की हमें जरूरत है। बुंदेलखण्ड में बहुत सैकड़ों छोटे बांध, बंधियां हैं, जो जर्जर पड़े हैं, उन जर्जर और ध्वस्त बंधे-बंधियों को कार्य योजना बनाकर पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। उनमें सिल्ट आ गई है। उस सिल्ट को हमें निकालने की आवश्यकता है।

स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई करने की योजना को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से सिंचाई करना कम्प्लसरी किया जाए ताकि पानी की बर्बादी न हो। इससे निश्चित तौर पर लाभ मिल सकता है।

महोदया, अन्ना प्रथा से हमारा क्षेत्र विशेष रूप से परेशान है। यह अन्ना प्रथा आज की नहीं है। बुंदेलखंड में हमारे यहां कहावत हुआ करती थी – 'बढ़ गयी

होली और छूट गयी घोड़ी।' चैत के महीने में होली से पहले हमारे यहां फसल कट जाती थी। अन्ना मतलब आवारा जानवर से है। हम लोग उनको पगही बोलते हैं और उनको रस्सी से छोड़ने का काम हम लोग करते थे। आषाढ़ में जब पानी गिरता था और होली के टाइम में जानवर आवारा कर दिए जाते थे, अन्ना कर दिए जाते थे। जब नागपंचमी की गुढ़िया का समय आता था तो गांव में मुनादी होती थी, ढोल पीटा जाता था कि अपनी-अपनी लाठी उठाइए। लाठी उठाने का मतलब युद्ध करने से नहीं था, बल्कि अपने-अपने जानवरों को चराने और संरक्षित करने की परम्परा थी। आज वह परम्परा पूरी तरह से समाप्त हो गई है। आज 12 महीने के लिए लोगों ने अपने जानवरों को छुट्टा कर दिया है क्योंकि खेती घाटे की हो गई है। एक फसली खेती है, वह भी भगवान भरोसे है। अगर बादल बरसेगा तो खेती होगी, अगर बदल नहीं बरसा और पानी नहीं आया तो बुंदेलखंड में सिंचाई का कोई साधन नहीं है, इसलिए खेती नहीं हो सकती है।

महोदया, पहले हमारा बैल उपयोगी हुआ करता था। मैं किसान हूं और सन् 1970 से 80 के बीच मेरे पास दस बैल थे। मैं उन बैलों से खेती करता था। मेरे पिताजी लगभग 50 गाय चराते थे। मुझे याद है सन् 1970 के करीब मेरा एक बछड़ा खो गया था। उस बछेड़े को ढूँढ़ने में हम लोगों ने एक हफ्ता लगाया था क्योंकि उस समय बछड़े की उपयोगिता होती थी, बैल की उपयोगिता होती थी। आज बैल की उपयोगिता न होने के कारण बछड़ों को लोगों ने छुट्टा छोड़ दिया है। जब तक गाय दूध देती है, तब तक हमारी और उसके बाद सरकारी। अन्ना जानवर हो गया, उसको सरकार देखे। यह परम्परा बन गयी है और इस परम्परा से निजात पाने के लिए हमें जन-जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।

महोदया, जब किसान के घर रिश्तेदार आता था तो पूछा जाता था कि बाल-बच्चे ठीक-ठाक हैं, तो वह कहता था – हां, ठीक-ठाक हैं। दूध-दूहान होता है, वह कहता था – हां, दूध-दूहान होता है। खेती-बाड़ी ठीक-ठाक है, वह कहता था – हां, खेती-बाड़ी ठीक-ठाक है। आज दूध-दूहान गायब हो गए हैं। आज किसान का बेटा खेत खलिहान में काम करने को तैयार नहीं है। आज उनके घरों में दूध नहीं बचा है। दूध वाली गाय सड़कों पर टहल रही है। अन्ना प्रथा हमारे लिए

अभिशाप बन गयी है। अभी हमारे कौशाम्बी के सांसद साथी सोनकर जी कह रहे थे कि बांदा-चित्रकूट के लोग अपनी फसल को बचाने के लिए गाय-बछड़ों को यमुना नदी के सहारे दूसरी तरफ पार करा देते हैं। रात-दिन किसान लाठी लिए अपने खेतों पर दौड़ता रहता है, तब भी फसल नहीं बचा पाता है। आज हमारी फसलें नष्ट हो गयी हैं। किसान अपने खेत को बोने को तैयार नहीं है। यह आज हमारे यहां अभिशाप हो गया है।

महोदया, पहले कर्मकांड में जन्म के समय बछिया दी जाती थी, मृत्यु के समय भी बछिया का दान-गोदान होता था। जब मेरी शादी हुई, उस समय मेरे बाबा जिंदा थे, उन्होंने कहा कि अच्छी और दुधारू गाय दहेज में चाहिए। उस समय दहेज में दुधारू गाय दी जाती थी। आज वह परम्परा बंद हो गयी है। आज गाय को कोई लेने को कोई तैयार नहीं है। हम किसी पंडित जी को गोदान में बछिया भी देते हैं तो वह नकद लेने को तैयार है, लेकिन गोदान की बछिया लेने को तैयार नहीं है। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां का यह मुद्दा है। मैं अभी असली मुद्दे पर तो आया ही नहीं हूं।

माननीय सभापतिः यह गलत है।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : आप असली मुद्दे पर नहीं जाकर गलत कर रहे हैं।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री आर. के. सिंह पटेल: सभापति महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के लिए कुछ सुझाव हैं कि गोसेवा भत्ता दिए जाने की कार्यवाही शुरू की जाए। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आवार गोवंश को संरक्षित करने के लिए 30 रुपये प्रति गाय और बछड़े के हिसाब से एक दिन में चारा-भूंसे की व्यवस्था करने का काम किया है। गांव सभावार प्रत्येक ग्राम पंचायतों में अस्थायी गोशाला खोलकर मनरेगा से गोवंश को संरक्षित करने वालों को गोसेवा

भत्ता दिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी, जो आवारा-बेसहारा गोवंश हैं, उनको चराने के लिए मनरेगा से मजदूर नियुक्त किए जाने की आवश्यकता है। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर पशु आश्रय गृह खोले जाने की आवश्यकता है। उनको सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाना चाहिए। गोवंश के गोबर और गोमूत्र को खरीदने हेतु न्याय पंचायत स्तर पर एक बाजार बनाया जाना चाहिए। हम जीरो बजट खेती के लिए जो काम कर रहे हैं, उससे जीवा मृत घोल और घन जीवा मृत घोल बनाकर किसानों के खेतों के लिए और उनको प्रोत्साहन देने के लिए काम कर सकते हैं।

माननीय मंत्री जी, देशी गायों को पालने वाले किसानों को स्पेशल प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता दिए जाने की आवश्यकता है। यह बिल अन्ना प्रथा पर आया है, इसलिए पशु गणना कराकर जो बेकार नस्ल वाले बछड़े हैं, उनको चिह्नित करके उनका बधियाकरण कराया जाना चाहिए। पूरे प्रदेश और पूरे बुंदेलखंड के किसानों को अच्छी नस्ल के बछड़े मुफ्त में दिए जाने की आवश्यकता है। आपने जो बछिया पैदा करने वाला बनाया है, मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं कि वह 90 प्रतिशत बछिया पैदा करेगा। वह मुफ्त में किसानों को दिया जाना चाहिए, चूंकि 100 या 200 रुपये उसका रेट रखा गया है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चहता हूं कि बछिया पैदा करने के लिए मुफ्त में दिया जाना चाहिए। जीरो बजट खेती पर बल दिया जाना चाहिए और जीरो बजट खेती पर किसानों को तैयारी करने के लिए उनको प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए।...(व्यवधान) किसान को कम से कम 10 से 15 हजार रुपये जीरो बजट खेती पर दिया जाना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : पटेल जी, अब आपका समय समाप्त हो चुका है।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री आर. के. सिंह पटेल : सभापति महोदया, एक कवि घाघ हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि – जेकरे खेत पड़ा नहीं गोबर, सो किसान को समझो दूबर। जिस किसान के खेत में गोबर नहीं पड़ता था, उस जमाने में वह किसान दूबर होता था। इसका मतलब वह फसल पैदा नहीं कर सकता था। घाघ कवि की

कहावतों के आधार पर हमारे बुंदेलखंड में दलहन, तिहलन और मोटे अनाजों की पैदावार होती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि मोटे अनाजों और दहलन-तिलहन पैदा करने वाले किसानों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।...(व्यवधान) बुंदेलखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, उसको केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है। वहां पर जो दलहन-तिलहन की फसले हैं, उनको उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वह दलहन-तिलहन का हब है।

अतः आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको और माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (**मेरठ**) : आदरणीय सभापति महोदया जी, आपका धन्यवाद। मैं आर. के. सिंह पटेल जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज अपना वक्तव्य थोड़ा समेट लिया है। वास्तव में, मैं प्रारंभ में ही हमारे पुष्पेन्द्र सिंह जी का इसके लिए अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का महत्वपूर्ण विषय, इसका प्रवर्तन इस लोक सभा के अंदर कराया है। उन्होंने बेशक अपने क्षेत्र की समस्या बताई है, केन-बेतवा को जोड़ने के बताई है और अन्ना पशु के संबंध में चर्चा की है।

परंतु इस चर्चा के बहाने पानी की जो समस्या है, और आवारा पशुओं की जो समस्या है और जो आज बहुत सीमा तक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, उसके ऊपर चर्चा को उन्होंने प्रोत्साहित किया और हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों में इस पर हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत अध्ययन के साथ, बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं सदन को उपलब्ध कराई हैं। पानी का क्या महत्व है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद बुंदेलखण्ड ही है। हमारे उपनिषदों में तो कहा ही गया है कि जलम् वई जीवनम्। विज्ञान भी मानता है कि कहीं किसी गृह पर, उपग्रह पर कोई जल है तो समझ लीजिए कि जीवन जरूर होगा। यानी जो सभ्यता की दृष्टि

से, परंपरा की दृष्टि से, विरासत की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र था, अत्यंत संपन्न क्षेत्र था, पानी की अपउपलब्धता के कारण से वहां क्या स्थिति पैदा हो गई है, इससे हमको ध्यान में आता है कि पानी का वास्तव में हमारे जीवन के लिए कितना महत्व है, जो सामान्यत: आज भी जहां पानी उपलब्ध है, वहां बहुत से लोग जाग्रत नहीं हैं। अब मैं तो मेरठ से आता हूँ। मेरठ गंगा-यमुना का दोआबा है। वहां पर पानी की कठिनाई को कोई सोच भी नहीं सकता था। परंतु आज वहां भी पानी की कठिनाई है। मेरठ जिले के 13 में से सात ब्लॉक डार्क जोन बन चुके हैं। यह पानी के संकट की स्थिति है। मैं पुष्पेन्द्र जी का इसीलिए अभिनन्दन करता हूँ कि इस समस्या को उन्होंने इस स्तर के ऊपर उठाने में मदद की है। हमारी सरकार बहुत जाग्रत है, जागरूक है। नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग एक समग्र दृष्टि के साथ सभी समस्यों का ध्यान रख के देश के अंदर योजनाओं को चला रहे हैं। पहली बार एक कैबिनेट मंत्री के साथ जल-शक्ति मंत्रालय का सृजन हुआ है। इसीलिए हुआ है कि जल से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनको समग्र रूप में देख कर उनका हल करने का प्रयास करें। जो विषय हमारे माननीय सांसद ने केन-बेतवा का या नदियों को जोड़ने का, मैं भी यह मानता हूँ, अभी हमारे अन्य कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा है कि नदियों को जोड़ने से कुलमिला कर के पानी का संकट तो संभवत: खत्म नहीं होगा। यह जरूर है कि उससे सिंचित क्षेत्र का विस्तार होगा। यदि नदियां जुड़ जाएंगी, कुछ बीच में नहर जैसी चीज़ें हमें निर्माण करनी पड़ेंगी, तो उसके कारण से पानी की उपलब्धता ऐसे क्षेत्रों को हो जाएगी, जहां अभी तक वह नहीं थी। मैं फिर से यदि मेरठ का उदाहरण दूं तो हमारे यहां गंगा से इतनी नहरें निकली हुई हैं, उसकी जो उप-नहरें निकली हुई हैं कि संपूर्ण क्षेत्र सामान्यत: नहर के या गंगा जी के पानी से सिंचित होता है। भूगर्भ जल का भी अब तो प्रयोग होने लग गया है, लेकिन मूलत: इन नहरों की वजह से सिंचित क्षेत्र का विस्तार हुआ है। वह उद्देश्य जरूर पूरा होगा, परंतु पानी का कुल जो संकट है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि पृथ्वी की पानी को धारण करने की जो क्षमता धीरे-धीरे खत्म होनी चली जा रही है, उसकी तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा।

माननीय, मुझे ध्यान है कि सत्तर के दशक में मैं गांवों के अंदर जाता था। मेरी पृष्ठभूमि, मैं संघ का बहुत समय तक प्रचारक के रूप में कार्यकर्ता रहा हूँ तो गांवों में जाता था तो कहीं पर भी बरसात के दिनों में खास तौर से कुंओं में एक डेढ़ हाथ लंबी रस्सी आप ले लीजिए और पानी निकाल लीजिए। परंतु अब यह संभव नहीं है। अब सारे कुंए सूखते चले जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि क्रमशः पानी को धारण करने की जो क्षमता है, वह हमारे क्षेत्र के अंदर पूरी की पूरी तरह से खत्म हो गई है। कुएं सूख गए हैं। जो तालाब हैं, वे गाद से भर गए हैं, गंदगी से भर गए हैं। आज स्थिति यह है कि प्रत्येक गांव के अंदर तालाब एक प्रकार से कूड़ा घर बन गया है। उसकी कभी सफाई नहीं होती है। उसकी वजह से पानी थोड़ी बरसात होने के बाद भी सारे गांव के अंदर पानी भर जाता है। हम अगर शहरों के अंदर भी देखें तो धारण क्षमता का आभाव इतन हो गया है, अब पानी के बरसने की मात्रा घट रही है, लेकिन पानी की वजह से थोड़ी बरसात होने के बावजूद भी दिल्ली में क्या हाल होता है, मुंबई में क्या हाल होता है, कोलकाता में क्या हाल होता है। ये तो बड़े नगर हैं। मेरठ में या प्रयाग में या झांसी में, छोटे-छोटे स्थानों पर भी वॉटर लॉगिंग हो जाता है, क्योंकि पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह जो संकट है, मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है। कई बार जैसे अभी हमारे अनुराग जी इस बात को कह रहे थे कि इसका जो आईआरआर है, वह 10 प्लस है। मुझे लगता है कि इस बात की तरफ भी देखे जाने की जरूरत है कि पानी अनियंत्रित हो कर जब भरता है, सड़कों पर बहता है, उसके कारण से कितना नुकसान होता है। इसका आंकलन किया जाना चाहिए। यद्यपि हो सकता है कि यह हो सकता है कि सीधे माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में न आता हो, परंतु सरकार के क्षेत्र में तो सारे विषय आते हैं।

इतनी सड़कें टूटती हैं, प्रत्येक वर्ष उन पर कितना रुपया खर्च करना पड़ता है। यदि हम पानी की व्यवस्था कर लें तो शायद आर्थिक दृष्टि से, जहाँ हमको सिंचित क्षेत्र मिल जाएगा, पेयजल के लिए हमको जो व्यवस्थाएँ करनी पड़ती हैं, उससे हम थोड़ा बहुत बचेंगे। लेकिन जो नुकसान होता है, उससे भी हमको कुछ

निजात मिल सकती है। इसलिए भी आकलन किया जाना चाहिए। वास्तव में यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

सांसद आदर्श ग्राम का विषय निकला। मुझे ध्यान है, जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने उसके विषय में बताया और उसकी लॉन्चिंग की गई, उन्होंने एक बात कही कि हम एक गाँव लें और वहाँ देखें कि सरकारी योजनाएँ किस प्रकार से काम करती हैं। हम सीधे काम करेंगे तो हमें कुछ अनुभव मिलेंगे और उन अनुभवों के आधार पर हमारी काम कराने की क्षमता भी बढ़ेगी। हमारी जानकारी बढ़ेगी, उन्होंने एक ऐसा विषय रखा था। हम लोगों ने गाँव लिए, हम जो कुछ भी कर सकते थे, हमने किया। अपनी निधि से भी कुछ काम करवाए, सरकारी योजनाओं से भी कुछ काम करवाए। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या गाँव के अंदर ध्यान में आई, जिसका हमारे पास हल नहीं था, जिसके कारण से मैं यह भी कह सकता हूँ कि कुछ अपयश भी मिलता था, गाँव के जो तालाब हैं, उनकी हम ठीक प्रकार से सफाई नहीं करवा पाए। कोई व्यवस्था नहीं थी। मनरेगा के अंतर्गत करें या कुछ पाँच, दस, बीस लोगों को इकट्ठा करके भी करें, कुछ तालाब बड़े भी हैं, उन पर कब्जे भी हुए हैं, लेकिन तालाब कुछ बड़े भी हैं, उनमें आप बिना मशीन के उनकी सफाई कर ही नहीं सकते। यह स्थिति है। मैं इस चर्चा के माध्यम से इस बात का अनुरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि आज तालाबों की सफाई प्राथमिकता पर है। मुझे ध्यान है, पिछले कार्यकाल के अंदर भी मेरे जिले के अंदर 100 तालाब चिह्नित किए गए थे कि इनकी सफाई की जाएगी। लेकिन किसी कारण से कुछ हो नहीं पाया। तालाबों की सफाई को मिशन मोड में लेकर, केवल मनरेगा पर सीमित रखने से काम नहीं चलेगा, मिशन मोड में लेकर उनको मशीनों से भी साफ करा कर, यदि तालाब हम गहरे कराएँगे, साफ कराएँगे तो पानी की धारण क्षमता भी बढ़ जाएगी। हम लोग उससे स्थाई समाधान की ओर बढ़ेंगे।

वृक्षारोपण का विषय बड़ा पुराना है, मैं उस पर ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं समझता। कुल मिलाकर मैं यह मानता हूँ कि नदी को जोड़ना, उससे सिंचित क्षेत्र का तो विस्तार होगा परन्तु धरती की पानी को रोकने की क्षमता है, जब तक वह नहीं बढ़ेगी तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी।

जो अन्ना पशुओं की बात है, यहाँ कारण दूसरा होगा, किसी अन्य क्षेत्र में कारण दूसरा होगा, लेकिन आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। पिछले चुनाव के अंदर इसके ऊपर थोड़ा बहुत मुद्दा भी बना। किसानों को तकलीफ थी, हम पर उनको भरोसा था, उनको यह लगता था कि हम इस समस्या का हल करने के लिए गम्भीरता के साथ प्रयासरत है। उन्होंने हम पर विश्वास किया। चुनाव का जो परिणाम आया, वह सब को पता ही है। लेकिन मैं यह समझता हूँ कि यह चुनौती भी है, यह एक समस्या है, यह एक बड़े समाधान की तरफ भी लेकर जाती है। आज स्थिति यह है कि हम ज़ीरो बजट खेती की बात करते हैं, उसका आधार मुख्य रूप से हम जैविक खेती की तरफ जाएँगे, तभी ज़ीरो बजट खेती का कान्सेप्ट उसके अंदर आता है। ज़ीरो बजट खेती होगी या कम बजट की खेती होगी, उसके अंदर हम जैविक की तरफ जाएँगे तभी वह हो सकता है। आज इसके इतने पहलू हैं, जो रासायनिक खाद प्रयोग करने की वजह से, पेस्टिसाइड्स प्रयोग करने की वजह से जहाँ धरती बीमार हुई है, पानी अशुद्ध हुआ है, पानी प्रदूषित हुआ है यानी हमारे सामने ये समस्याएँ हैं। धरती की जो उर्वरक क्षमता है, उसको नुकसान हुआ है। यदि समग्र दृष्टि से सोचें और इस सरकार की विशेषता है कि यह सरकार किसी भी समस्या पर आइसोलेटेड ढंग से विचार नहीं करती, उसके सारे पहलुओं पर विचार करती है। यदि हम गोबर का उपयोग धीरे-धीरे बढ़ाते चले जाएं, यूरिया का या कृत्रिम रासायनिक खादों का प्रयोग धीरे-धीरे कम करते चले जाएं तो जहाँ एक ओर धरती की उर्वरक क्षमता सुधरेगी, जहाँ पानी शुद्ध बना रहेगा, जहाँ पर भोजन के अंदर जो तत्व हैं, वे अच्छे हो जाएँगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ। हम लोग बचपन में कहा करते थे कि सेब को बगैर छीले खाना चाहिए। छील कर नहीं खाना चाहिए। यदि कोई छील देता था, आपने भी ये बातें सुनी होंगी, मैं उम्र में थोड़ा सा बड़ा हूँ, ये बातें सब को ध्यान होंगी कि सेब के बारे में कहा जाता था कि छिलका छील दिया तो वे कहते थे कि तुमने तो विटामिन निकाल दिए, ऐसा वे मज़ाक करते थे और बात मानी जाती थी कि सेब को छिलके सहित खाना चाहिए। हम बड़ी प्रसिद्ध कहावत सुना करते थे- An apple a day keeps doctor away. लेकिन आज स्थिति यह है कि यदि एक सेब छिलके के साथ खा लिया जाए, रोज़ खा लिया जाए तो महीने भर के अंदर उसको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना पड़ेगा। उसको

कोई भी रोग या बीमारी हो सकती है। इसकी लगभग गारंटी उसके हो जाती है। जो खाद्य सामग्री है, वह प्रदूषित हो रही है। जल है, वह प्रदूषित हो रहा है, धरती है, वह प्रदूषित हो रही है और इसलिए ये जो हमारे पशु हैं, जैसा कि अभी योगी जी की सरकार का जिक्र हमारे आर.के. सिंह पटेल साहब कर रहे थे कि इनके लिए चारागाह बनाए जाए।

17.55 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

इनके लिए ऐसे स्थान सुनिश्चित किए जाएं, जहाँ पर ये पाले जाएं। जैसे हम लोग रासायनिक खाद के ऊपर सब्सिडी देते हैं, सरकार इसको भी सब्सिडाइज करे, वहाँ पर उस प्रकार की खाद बनाई जाए, वहाँ वर्मी कंपोस्ट का निर्माण हो और उसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन भी हो सकता है। कुल मिलाकर यदि समग्र रूप से हम इसका विचार करेंगे, तो हमारी धरती भी अच्छी हो जाएगी, पशुओं की भी चिंता का हल निकलेगा, खाद का निर्माण भी हो जाएगा, हम केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग को भी कम कर सकेंगे और हमारी खाद्य सामग्री भी ठीक हो पाएगी। यदि हम इस चुनौती का उपयोग अवसर के रूप में करें, तो मैं समझता हूँ कि इसका उपयोग होगा। मैं इस चर्चा को शुरू करने के लिए एक बार पुनः चंदेल जी को धन्यवाद देता हूँ और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने कोशिश की है कि बहुत कम समय में अपनी बात पूरी कर सकूँ।...(व्यवधान) अभी एक वक्ता और हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : आप चाहें तो मैं सभा की कार्यवाही 2-3 घंटे तक बढ़ा सकता हूँ।

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल): महोदय, जितने मंत्री यहाँ बैठे हैं, उतने तो सांसद भी यहाँ नहीं हैं।

श्री नायब सिंह सैनी (कुरूक्षेत्र): आदरणीय अध्यक्ष जी, आज मुझे एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मुझे बोलने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश का एक बहुत ही अहम विषय, सबसे पहले उन्होंने 2014 से 2019 तक स्वच्छता अभियान के द्वारा देश को जागरूक करने का काम किया और उसके बाद उन्होंने हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना का आगाज किया था। वह भी एक महत्वपूर्ण विषय था और देश की जनता के दिलों को छूने वाला विषय था। उससे देश जागरूक हुआ।

अब आदरणीय प्रधान मंत्री जी द्वारा अलग से एक जल शक्ति मंत्रालय बनाकर इस विषय में देश को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इससे आने वाले समय के अंदर, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से स्वच्छता के अभियान के अंदर पूरा देश जुटा, जागरूक हुआ, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर देश जागरूक हुआ, उसी प्रकार से इस जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से भी देश जागरूक होगा। देश के सामने एक बड़ी चुनौती आने वाले समय के अंदर जल के संबंध में आने वाली है। इसकी चिंता आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने देश के समक्ष रखी और जल शक्ति मंत्रालय बना कर लोगों को जागरूक करने और इस समस्या का समाधान करने का कार्य कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं को आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी पिछले वर्ष हमारे यहां पर सरस्वती नदी का प्रवाह, जो विलुप्त हो चुकी थी, परन्तु नासा की रिपोर्ट के अंदर भी उस सरस्वती नदी का प्रवाह नीचे दिखाया गया था। उसके ऊपर काम भी चला और जब आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी हरियाणा के अंदर सरकार बनी, तो अलग से उसका एक बोर्ड भी बनाया गया – सरस्वती हैरिटेज बोर्ड। वह बोर्ड बनाकर के उस सरस्वती नदी के ऊपर काम चालू किया गया। आदरणीय नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री थे, आदि बद्री जहां सरस्वती नदी का उदगम स्थल है, वे वहां आए थे और वहां पर एक बांध की उन्होंने घोषणा की थी। यहाँ पर यह बांध बनेगा

और सरस्वती के ऊपर जो काम लग रहा है, यह नदी हरियाणा की जीवन रेखा है, हरियाणा के बीच से यह नदी निकलती है, उसके अंदर 12 महीने पानी उस बांध के माध्यम से मिलेगा ।

18.00 hrs

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर उस काम को थोड़ा जल्दी करके तेजी से काम चालू किया जाएगा तो वह नदी प्रवाह में आ जाएगी। इससे हरियाणा के किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना भाषण अगली बार जारी रखेंगे।

सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.01hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, July 22, 2019/Ashadha 31, 1941 (Saka).

-

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

** Introduced with the Recommendation of the President.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 406/17/19.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* English translation of speech originally delivered in Telugu.